उपसभापति : श्री कृष्ण लाल शर्मा । शर्मा जी, हम लोग साढे चार बजे शुरू कर रहे हैं और तीन घंटे दिए हैं । वैसे तो आपकी पार्टी के 23 मिनट हैं, लेकिन अगर आप अपनी बात संक्षेप में कह सकें यही बातों को तब हाउस आपका आभारी होगा ।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : कुल कितना टाइम है ?

उपसभापति : तीन घंटे हैं । उसमें दो मंत्रियों का भाषण भी शामिल है । दो मंत्रियों का तो 3 घंटे में से एक घंटा तो चला गया । इस प्रकार दो घंटे ही बचे । ....(**व्यवधान**) No; we have got so much business. अभी रेलवे का आ गया है । कल का दिन अकेला रह गया है । तो किसी भी हालत में आज ही इसको खत्म करना है ।

I. STATUTORY RESOLUTION SKKK1NG APPROVAL OF THE CONTINUANCE IN FORCE OF PRESIDENT'S PROCUMATION IN RELATION TO THE STATE OF JAMMU AND KASHMIR

II. THE JAMMU AND KASHMIR APPROPRIATION (NO. 2) BILL, *1993-Contd*

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : उपसभापति महोदया, इस समय जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1993 और जो राष्ट्रपति द्वारा धारा 356 के अंतर्गत 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा थी उसे 31 सितम्बर के बाद 6 महीने के लिए और राष्ट्रपति शासन जम्मू-कश्मीर में बढ़ाने के लिए यह दोनों विषय संयुक्त चर्चा के लिए इस समय सदन में प्रस्तुत है ।

मैं पहले जम्मू-काश्मीर विनियोग विधेयक के संबंध में कुछ बातें कहूंगा महोदया, हमारे इस विनियोग विधेयक में जो बातें जम्मू-काश्मीर के संबंध में कही गयी हैं, इसमें एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि यह जो करोड़ो रुपए हम खर्च कर रहे है जम्मू-काश्मीर पर, वह कहां जा रहा है ? अगर संबंधित मंत्री महोदय कोई परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा बता दें तो ठीक रहेगा कि पहले जो हमने धनदान दिए वह कहां खर्च हुए और वह खर्च हुए तो संतुलित रूप से खर्च हुए, विकास कार्यों में खर्च हुए या कहीं और चले गए क्योंकि इससे कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आती है । महोदया, जम्मू-काश्मीर का मामला वित्त के सम्बन्ध में ऐसा हो गया है कि शायद यह डिवीजन ऑफ लेबर है कि जितनी रेवेन्यू है, जितनी इनकम है वह तो जम्मू और लद्दाख रीजन से प्राप्त होती है और जितना खर्चा होता है, वह काश्मीर वैली पर होता है । मैं वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वह अगर इस बात को स्पष्ट करें कि पिछले तीन वर्षों में या कम से कम इस वर्ष में हमें जम्मू-काश्मीर के पूरे प्रदेश का नहीं तो केवल काश्मीर वैली में से कितना रेविन्यू प्राप्त हुआ और किस-किस मद में प्राप्त हुआ ? हमारी जानकारी के हिसाब से तो न कोई वहां बिजली का बिल देता है, न दूसरे विषयों के लिए बिल देता है । वहां पर कोई भी नियम लागू ही नहीं है, कोई टैक्स या किसी प्रकार की और चीज घाटी पर अगर लागू है, तो इस बारे में आप जानकारी दें । फिर मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस सारे विनियोग विधेयक में इस समय जो जम्मू-काश्मीर की बहुत बड़ी समस्या है विस्थापितों की, इसमें कोई पैसा उसके लिए रखा नहीं गया है । अगर रखा गया है तो वित्त मंत्री महोदय मुझे बताएं । करीब ढाई लाख विस्थापित वहां से निकाले गए हैं जोकि जम्मू में हैं, बाहर भी हैं और उसके लिए इस विनियोग विधेयक में कोई पैसा ही न हो, यह एक आश्चर्य की बात है । दूसरी बात, पर्यटन के लिए पैसा रखा गया है । मैं जानना चाहता हूं कि पर्यटन का पैसा कहां खर्च हो रहा है ? मेरी जानकारी के हिसाब से तो कोई पर्यटन की एक्टिविटी या सक्रियता काश्मीर घाटी में इस समय नहीं है और जहां पर्यटन की कोई एक्टिविटी है वहां उनको सहायता नहीं है । महोदया, इस समय जम्मू-काश्मीर में सबसे बड़ा अगर पर्यटन का कोई स्थल है तो वह वैष्णो देवी की यात्रा है । जम्मू से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू के लिए कोई हवाई जहाज प्रोवाइड हम नहीं दे रहे हैं । इसके अलावा भी पर्यटकों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, उस दृष्टि से कुछ सोचा नहीं जा रहा है । एजुकेशन और अनेक जरूरी मुद्दों पर भी कोई खर्च नहीं हो रहा है । मेरा यह निवेदन है कि जम्मू-काश्मीर की समस्या का समाधान इसमें है कि पहली बात जो भी पैसा लेते हैं वह तीनों क्षेत्रों—काश्मीर घाटी, जम्मू क्षेत्र और लद्दाख क्षेत्र, इनके लिए अलग-अलग पैसा विकास-

(उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) पीठासीन हुए)

कार्यों के लिए दिया जाए और इस बारे में परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाए कि वह अलग-अलग कार्यों पर कहां-कहां खर्च हुआ और कहां-कहां उसका उपयोग हुआ ? नहीं तो आज ऐसी स्थिति बन गयी है कि जहां हम घाटी में पैसा लगा रहे हैं वह तो नष्ट हो रहा है । यहीं तक नहीं, वह पैसा आतंकवादियों के पास जा रहा है । विकास के नाम का पैसा आतंकवादियों के पास पहुंच रहा है जिससे कि वे शस्त्र ला रहे हैं और भारत के खिलाफ उनका उपयोग हो रहा है और जहां जम्मू में, लद्दाख में जो पैसा खर्च होना चाहिए वह हम खर्च नहीं कर रहे हैं । तो मेरा निवेदन यह है कि विस्थापितों के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए । पर्यटन के लिए जो पैसा है, वह जम्मू क्षेत्र में, लद्दाख क्षेत्र में भी खर्च होना चाहिए और कुल मिलाकर तीनों क्षेत्रों के संतुलित विकास की योजना बननी चाहिए और उसके लिए पैसा दिया जाना चाहिए अन्यथा यह विनियोग विधेयक पक्षपातपूर्ण माना जाएगा ।

एक बात और कहना चाहता हूं । आप यह छह महीने के लिए और राष्ट्रपति शासन बढ़ा रहे हैं । चव्हाण साहब यहां उपस्थित हैं । गृह मंत्रालय में भी शायद काम बंटा हुआ है । स्थिति सुधरी है और चुनाव कराने के लिए वातावरण अनुकूल है, यह वक्तव्य अगर देना होगा तो दूसरे मंत्री आएंगे । वह आज नहीं है यहां । आज चव्हाण साहब कह रहे हैं कि वहां परिस्थिति

ऐसी है कि वहां छह महीने के लिए और राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाए । वहां परिस्थिति खराब है । बीच में यह भी कहा गया कि कुछ कुछ सुधार भी है । अब मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई भी, एक भी पक्ष ऐसा बताया जाए जम्मू-काश्मीर में और खासतौर पर कश्मीर घाटी में, जिसमें हम यह समझते हैं कि उसमें सुधार हो रहा है । मेरी जो जानकारी है, मेरी जो रिपोर्ट है, वह मेरे मन में एक गम्भीर चिंता और आशंका पैदा करती है कि वहां परिस्थिति सुधर नहीं रही है, परिस्थिति खराब हो रही है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अजीब तरह की चीजें हो रही हैं । चन्द्रशेखर साहब ने एक संयुक्त और संसदीय दल भेजा था 22, 23 और 24 जुलाई को वह लद्दाख की यात्रा के लिए गए थे, जुलाई में, इसी सत्र के शुरू होने से पहले । वहां पर गवर्नर साहब ने उनके सामने विचार रखे । राज्यपाल महोदय ने कहा, कुछ शब्द ऐसे उन्होंने कहे जिस पर मुझे बहुत आपत्ति है, उन्होंने पहले तो यह कहा कि हम दिसम्बर तक चुनाव करवाने वाले हैं । यह हमारे जो संसदीय दल के लोग गए थे उनसे आप पूछ लीजिए, इसको आप कन्फर्म कर लीजिए । उन्होंने कहा कि हम दिसंबर तक चुनाव करवाने वाले हैं । इससे भी आगे एक और बात इतनी गैर-जिम्मेदारी से उन्होंने कही कि मैंने इसके लिए सेना को बता दिया है । जम्मू-कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं दिसम्बर में और गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मैंने सेना को बता दिया है कि दिसंबर में चुनाव करवाएंगे । यह उन्होंने एक सबूत गैर जिम्मेदारी का दिया । यह एक ऐसे सेंसटिव एरिया में गवर्नर बैठे हुए हैं । उसके बारे में हमें क्या कहना चाहिए । गवर्नर साहब का एक बार फिर स्लिप आफ टंग हो गया, 15 अगस्त को बोलते हुए, उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि कश्मीर भारत के साथ कभी नहीं जुड़ सकता और बाद में स्पष्टीकरण हुआ कि नहीं, वह कह रहे थे कि भारत से कभी छूट नहीं सकता । लेकिन, उनके शब्द यह थे कि वह कभी जुड़ नहीं सकता । अब मैं यह समझना चाहता हूं कि वह वहां पर क्या कर रहे हैं ?

उपसभाध्यक्ष महोदय, वहां के गवर्नर के बारे में भी अपना इतिहास है । गृहमंत्री महोदय बैठे हुए हैं । हमें आप बताएं कि आपने तीन गवर्नर बदले, एक जगमोहन जी पहले पांच-छह महीने के लिए रहे, जो आज हमारे बीच में हैं, वह वहां से चले गए उसके बाद सक्सेना जी आए, तो जगमोहन जी के जाने के बाद क्या वहां स्थिति सुधरी या बिगड़ी ? मेरे हिसाब से एक गवर्नर आप बदलते हैं और दूसरा आता है तो स्थिति और बिगड़ जाती है । अब यह जो नए गवर्नर आए हैं, इनके आने के बाद स्थिति और बिगड़ गई है । अगर ऐसे ही स्थिति का हमें सामना करना है तो मुझे लगता है कि हमारा भगवान ही मालिक है । अगर इसके बारे में कोई जानकारी ही देना हो तो उस जानकारी के लिए मैं आप सबके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा । अमरनाथ की यात्रा के समय आतंकवादियों ने यात्रियों पर पहली बार आक्रमण किया और इस आक्रमण में एक यात्री तो मरा और 23 घायल भी हुए । आप इस समय जितनी भी वहां की स्थितियां ले लें, वह बिगड़ी है । श्रीनगर कर्फ्यू में है, लेकिन कर्फ्यू का खुल्लमखुल्ला वायोलेशन हो रहा है । कोई उनको पूछने वाला नहीं है ।

महोदय, वहां पर कितने लोग मारे गए हैं ? इसकी अगर सूची निकाली जाए और उसकी जानकारी अगर दी जाए तो मैं समझता हूं कि गृहमंत्री महोदय भी उसकी थोड़ी चर्चा अपने उत्तर में करेंगे । पिछले दिनों में सुरक्षाकर्मी यानि सिक्युरिटि फोर्सेस के 117 जवान मरे हैं, राजनीतिक 4 मरे हैं, सामान्य नागरिक 857 मरे हैं, भारत सरकार के कर्मचारी 36 मरे हैं, पत्रकार एक मरा है । यह स्थिति सुधर रही है ? कुल मिलाकर हमारे इस प्रदेश में 4,971 हिंसा की घटनाएं हुई हैं । मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं । सुरक्षा बलों पर 3413 आक्रमण हुए हैं । इसी से आप अंदाज लगाइए कि कितनी हिम्मत, कितना साहस वहां आतंकवादियों में है । और अन्य जो आक्रमण हुए हैं वे 507 हैं और वहां पर जो विस्फोट हुए हैं, वह 307 है । यह परिस्थिति वहां बनी हुई है और हमारे कुछ मित्रों को अच्छा नहीं लगेगा और वह जब भी कोई विषय खड़ा होता है तो उनको संतोष तभी होता है जब उसमें वह 6 दिसम्बर को लाते हैं । अब यहां सारे सदस्य उपस्थित हैं, सरकार भी उपस्थित है, हो सकता है वे यह कहें कि जम्मू और कश्मीर में भी जो कुछ हो रहा है, वह 6 दिसम्बर की वजह से हो रहा है और उससे पहले सब शांत था । यह 6 दिसम्बर के बाद हुआ है और वे भारतीय जनता पार्टी पर भी शायद आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं यह बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर की जो परिस्थिति है वह रोजाना, दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है । कल तक आतंकवाद की समस्या केवल कश्मीर घाटी में थी, उसके बाद वहां से बढ़कर वह डोडा जिले में गई, डोडा जिले से आगे बढ़कर जम्मू क्षेत्र में गई, अब डोडा जिले के रास्ते से वह हिमाचल की तरफ भी और चंबा जिले के साथ लगे हुए इलाकों में भी आतंकवाद की समस्या बढ़ रही है । कुछ वायदे किए हुए हैं सरकार ने, वह उनको पूरा करने के लिए तैयार नहीं है । डोडा जिले में कंटोनमेंट बनेगा, यह कब से वायदा किया हुआ है, कंटोनमेंट क्यों नहीं बनता ? हम कहते हैं कि डोडा जिले में परिस्थिति को संभालने के लिए कुछ समय के लिए ही सही, उस जिले को सेना के हवाले कर दिया जाए । अगर आप कंटोनमेंट तुरन्त नहीं बना सकते तो तम्बू वगैरह लगाकर टैम्पोरेरी बेसिस पर कोई व्यवस्था कीजिए और वहां पर कम से कम आर्मी की जो उपस्थिति है, वही वहां पर लॉ एंड आर्डर को संभालने में मदद करेगी, लेकिन हम वह भी करने को तैयार नहीं हैं और दूसरी तरफ हम बार-बार यहां घोषणाएं कर रहे हैं । और चन्द्रशेखर साहब यहां पर धर्म से राजनीति को अलग करने का बिल लाएं । धर्म का उपयोग करने वालों पर वह चाहते थे कि यह पाबंदी लग जाए कि वे चुनाव न लड़े, लेकिन इस बिल में उनकी यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि कोई अगर सैसेशनिस्ट है तो उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, कोई अगर वायलेंस के साथ कानून को अपने हाथ में लेता है, राष्ट्रध्वज का अपमान करता है, राष्ट्रगान का अपमान करता है, वह चुनाव नहीं लड़

सकेगा, यह कहने की हिम्मत नहीं है उनकी । इसलिए वहां पर निमंत्रण दिए जा रहे हैं कि आइए, चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो जाइए । आप पाकिस्तान के साथ जैसा भी व्यवहार करें, भारत के बारे में जो कुछ भी बोलें, उनको निमंत्रण दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो लोग देश भक्ति के लिए और खास करके जम्मू-कश्मीर में जिनका इतिहास है, आपको अच्छी तरह से मालूम है, उनको धमकियां दी जा रही हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार इन संकेतों को बंद करेगी, यह जो गलत संकेत दिए जा रहे हैं ? जो लोग हमारे देश के टुकड़े करना चाहते हैं या भारत से कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, उनसे हमें बातचीत करनी चाहिए ? उनको हम चुनाव के लिए निमंत्रण देंगे ?

अभी 15 अगस्त को 250 लोग जेलों में से छोड़ दिए गए । किस खुशी में छोड़े गए ? क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया ? आज तक जो लोग जेलों में से छोड़े गए हैं, क्या हथियार एक तरफ रखकर वे शांतिपूर्ण जीवन में शामिल हो गए ? क्या एक भी उदाहरण मंत्री जी दे सकते हैं कि जो लोग जेलों से छोड़े गए, वे अब शांति से रहते हैं और किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे भारत सरकार को कोई चिंता हो ?

मुझे मन में बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे प्रधान मंत्री ने लाल किले से यह घोषणा की कि पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाए, मैं प्रधान मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वे यह बताएं कि उनको कश्मीर याद है या नहीं ? उनको प्रधान मंत्री बने हुए दो साल से ज्यादा का समय हो गया है, उनको एक भी दिन वहां जाने की फुर्सत नहीं मिली । क्या कश्मीर उनकी विषय-सूची में है या नहीं ? क्या कश्मीर का कोई महत्व उनकी लिस्ट में या महत्वपूर्ण विषयों में है या नहीं ? एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की नीयत खराब है और पाकिस्तान को अगर चुनौती देनी है तो मैं अपनी सरकार को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस देश का एक-एक व्यक्ति, हरेक पार्टी, पाकिस्तान के साथ कड़ा व्यवहार करने के लिए और कश्मीर के मामले पर उनकी सारी चुनौतियों का जवाब देने के लिए, अगर वह कोई भी संघर्ष करेंगे, कोई भी लड़ाई करेंगे, सारा देश आपके साथ है, यह सारी बात आपके विश्वास को बढ़ाने वाली होनी चाहिए ।

लेकिन लगता यह है कि जब कोई ऐसा समय होता है तो वह बाकी दलों को विश्वास में नहीं लेते । मुझे नहीं मालूम कि कोई ऑल पार्टी मीटिंग कभी की हो, जबकि इतनी बड़ी-बड़ी गंभीर परिस्थितियां पैदा हो गई ? नहीं, ऐसी कोई मीटिंग यहां पर नहीं हुई । हम कई बार कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री में एक कोर ग्रुप बन जाए, जो डे-टू-डे मौनिटरिंग करे और जो लोग जम्मू कश्मीर के साथ संबंध रखते हैं या आते-जाते हैं, उनको भी उसमें शामिल किया जाए । गृह मंत्री महोदय, इस सुझाव पर विचार करेंगे तो अच्छा है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति को भेजा । यह समिति कश्मीर भी गई, यह समिति लद्दाख भी गई । लेकिन जम्मू में जाने का उसको समय नहीं मिला । इस बार जब वह गई तो 4-5 घंटे उनको जम्मू के लिए मिले । न विस्थापितों के कैम्प देखने के लिए वह गए और न डोडा जिले में जो गंभीर परिस्थिति थी, उसको देखने के लिए गए और जम्मू से ही तुरन्त वापिस आ गए । गृह मंत्री महोदय से मैं फिर यह आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि वे विशेष रूप से संयुक्त समिति का एक दल फिर से भेजें जो केवल जम्मू में ही जाए और वहां जम्मू की समस्या तथा डोडा जिले की समस्याओं का अध्ययन करके गृह मंत्रालय को आकर रिपोर्ट दे और उसके बारे में उनके सामने वह चीजें रखें, जिससे कि वह सारी परिस्थिति को ठीक तरह से समझ सके । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस समय आई० एस० आई० जो पाकिस्तान की तरफ से है, वह बड़ा षड़यंत्र कर रहा है । उन्होंने तीन योजनाएं बनाई हैं । एक तो यह है कि दक्षिण एशिया से केवल जो गुरिल्ला या मर्सनरीज हैं वह केवल अफगान तक सीमित नहीं है, मर्सनरीज जो हैं वह कई देशों से यहां पर आए हैं और जो रिपोर्ट है कि इस समय तक 400 से ज्यादा ट्रेंड आकायदा ऐसे मर्सनरीज, विदेशी वह हमारे कश्मीर के इलाके में घुसे हुए हैं । उसमें से लगभग आधे अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं । लेकिन जो बाकी हैं वह सूडान से हैं, सऊदी अरब से भी हैं, बहरीन से भी हैं और भी कुछ जगहों से हैं । तो क्या सरकार के पास उनके बारे में कोई रिपोर्ट है और क्या सरकार उसके बारे में कोई कदम उठाने के लिए कुछ सोच रही है और कोई कदम उठा रही है, तो वह हमको बताए कि उन्होंने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं ?

अभी पहले से ही यह घोषणाएं करदी गई कि जम्मू कश्मीर के लिए 14 अगस्त से 17 अगस्त तक का समय बहुत क्रूसियल है, बहुत संकटपूर्ण है । इन्हीं दिनों में 14 अगस्त को वहां पर पाकिस्तान-डे मनाया जाता है जब पाकिस्तान के झंडे लगाते हैं । 15 अगस्त को काला दिन मनाया जाता है जो भारत की आजादी का दिन है तथा भारत के झंडे का, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जाता है । 17 अगस्त को जियाउल हक की हत्या हुई थी, उसका भी दिन वहां मनाया जाता है । वहां की यह सारी सूचनाएं होने के बाद भी वहां प्रशासन इतना पंगु रहा कि किस्तवाड़ में यह घटना हो गई तथा सड़क पर ही बस को एक किनारे पर ले जाकर उसमें 16 लोग जो एक ही समुदाय के थे, उनको बस से उतारकर उनकी हत्या कर दी गई और सरकार ने अभी कोई कदम नहीं उठाया है । किस्तवाड़ में घटनाएं हुई हैं, गोलीकांड हुआ है और वहां पर जांच के लिए सरकार ने आश्वासन दिया, अब तक कोई जांच नहीं हुई । वहां पर लोग मर रहे हैं और जो लोग मरते हैं उनको कम्पेंसेशन तक नहीं मिलता तथा कम्पेंसेशन देने के बारे में भी पक्षपात किया जाता है और जो लोग देश के अनुकूल, देश के हित में कोई रिपोर्ट देते हैं तो उनको कोई सुनने वाला नहीं है । मैं यह चाहता हूं कि वहां प्रशासन में, सेंसेटिव एरियाज में ऐसे लोग होने चाहिए जो स्थिति को संभाल सकें । मैं यह चाहूंगा कि अगर आप जम्मू कश्मीर की स्थिति को संभालना चाहते हैं तो भगवान के लिए कुछ समय के लिए पूरा बोर्डर जो इण्डो पाक बोर्डर है—भारत पाक बोर्डर है, उसको पूरी तरह से सील कीजिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी छूट दीजिए, ताकि वह वहां की परिस्थितियों को संभाले ।

हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हों, हम यह भी चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हों । लेकिन चुनावों के लिए वायुमंडल अनुकूल बनना, यह पहला काम है । पहले वहां पर नार्मलसी होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, फिर वहां पर चुनाव होने चाहिए । अगर चुनाव के बारे में अभी कोई अंधेरे में कदम उठाया गया तो उसके नतीजे अत्यंत खतरनाक हो सकते है ।

महोदय, मै यह भी कहना चाहता हूं कि कश्मीर के बारे में जब हम लोग सोचते है तो आइ० एस० आइ० के बारे में हमारा कोई जवाब नहीं है । जो वहां पर इस समय और पिछले दो तीन सालों से घटनाएं हुई है, 1100 बार पाकिस्तान ने हमारे बार्डर पर फायरिंग की है और मै यह जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है ? मेरे पास जो एक बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट है वह यह है कि हमारी दो चौकियां अंगल टेकरी और दोलक जो कि 1990-91 तक हमारे पास थी अब उन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और ये चौकियां पाकिस्तान के पास है और हमें सरकार यह बतानी नहीं है कि वहां पर क्या परिस्थिति है । हम देश को अंधेरे में रख रहे है ! पाकिस्तान बार्डर पर फायरिंग कर रहा है, आतंकवादी कश्मीर की घाटी में अस्थिरता पैदा कर रहे है और आतंकवाद को फैला रहे है, वह जम्मू में डोडा की तरफ बढ़ रहे है और हम अपने प्रचार के मोर्चे पर भी विफल हो रहे है । अभी कुछ दिन पहले वियाना में ह्यूमन राइट्स के बारे में एक सम्मेलन हुआ था । वहां पर पाकिस्तान ने जो तथ्य उपस्थित किए वह अधिक प्रभावी थे । हम अपना पक्ष भी वहां पर ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाए । मैं आज भी गृह मंत्री से कहना चाहता हूं कि इस सदन को विश्वास में लेते और कश्मीर की सही स्थिति के बारे में सदन को बताते और इसके साथ ही सही व्यक्ति हम अपने देश और विदेशों में अपने प्रचार के लिए भेजे । ....

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra) Sir, I am on a point of information. The Press Council of India, of which I happen to be a member representing Rajya Sabha, has come out with a very fine report on the human right situation in Kashmir. It has gone in detail into the human rights aspect. It has gone into all the complaints against the security forces. I think this report should be circulated on a very large-scale all over the world.

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस को नोट करें और इसके बारे में गंभीरता से सोचे ।

मंत्री महोदय, एक छोटी सी बात और है, आपके खिलाफ एक प्रिविलेज का मोशन भी है । आपने यह कहा था हमें कि जम्मू कश्मीर में केवल दो मंदिरों का मामला है । मेरे रिपोर्ट के मुताबिक हमको 1986 से अब तक की जानकारी है कि वहां पर 93 टैंपल्स पर आक्रमण हुए है, तोड़े गए है या उनको क्षति पहुंची है और अभी पिछले दिनों 52 टैंपल्स के बारे में रिपोर्ट है, एफ० आइ० आर० दर्ज हुई है । सरकार के पास उसका रेकार्ड है । आप यह रेकार्ड मंगवाएं और हमको पूरी जानकारी दें कि वास्तव में आपके पास क्या रिपोर्ट है, वहां पर मंदिर तोड़े गए हैं या नहीं । यह तो नहीं होना चाहिए कि अगर एक स्थान को क्षति पहुंची तो सारा आवेला मच जाए और दूसरे क्षेत्र में इतना बड़ा नुकसान हो तो सरकार भी न बोले, कोई दल वाले भी न बोलें ।

विस्थापितों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वहां कब तक स्थिरता आएगी, कब वहां पर चुनाव होंगे । क्या वहां के विस्थापित लोग तंबुओं में ही पड़े रहेंगे । कब तक उनको नौकरियां मिलेंगी, कब उनको अपना स्थान मिलेगा । अगर आप जम्मू कश्मीर की स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो जिन लोगों ने देश की एकता और अखंडता के लिए कष्ट उठाए है उनकी सहायता कीजिए, उन को विश्वास में लीजिए । अगर आप आतंकवाद से ही समझते है कि वही लोग हमारा भविष्य बनाएंगे तो मुझे अफसोस है कि हमें गलत फहमी है ।

श्रीमान, मैं इस विनियोग बिल का समर्थन कर रहा हूं क्योंकि आखिर प्रदेश के कामकाज के लिए पैसा चाहिए । वहां पर राष्ट्रपति शासन का भी मै समर्थन करता हूं । लेकिन मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी है । देश की एकता और अखंडता को लेकर आज कश्मीर संकट मे है और देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए कश्मीर का बचाना बहुत जरूरी है और अगर कश्मीर बचाना है तो उस के लिए दलगत आधार नहीं होना चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए ।

दलगत विषयों से ऊपर उठकर सब दलों को विश्वास में लेकर आप संयुक्त कोई कार्य योजना बनाइये । उसमें हम भी सहयोग देंगे । फिर से मैं एक बात दोहराना चाहता हूं कि जम्मू क्षेत्र को यह आभास मत होने दीजिये कि आप दुर्व्यवहार कर रहे है और पक्षपात कर रहे है । उसके अध्ययन के लिए आप एक संसदीय समिति भेजिये और वह समिति जाकर रिपोर्ट लाये और आपके सामने पेश करे । इन शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Sir, periodically, we deal with the issue of Kashmir. But, I do not think that in the last two years the situation was as grave as it is today there and it has deteriorated perticularly from the 1st of August when a couple and their ten-year old boy were killed by the BSF. Thereafter, there have been announcements on the loudspeakers from the mosques and the people have come out in thousands and in the grim situation that is there there is no letup, and what was mentioned, on which we had expiessed our anxiety a few days earlier, is the event of killing of bus passengers on the 14th of August in Doda district. It was only a sort of culmination of the determined bid on the part of the anti-national forces against us.

Now, Sir, we must get our priorities correct

because what is most confusing is (he manner in which, at one time, we hear that there will be elections and almost without any big interval, there is again a statement from the Government that there will be no elections. I think our perceptions about democracy and militancy must be clear. The dividing line to us is quite clear. Militancy and insurgency are an anathema to democracy. Democracy assumes that there will be an orderly and lawful life, peaceful life, for all the residents of any locality. Now, it is not merely a case like that of Punjab or Assam where there is only the problem of militancy and insurgency. Kashmir is a far graver case because it is a case of a proxy war which has been launched by Pakistan against us. Therefore, it is not as if the people of Kashmir are responsible for what is happening in that Valley. What is really happening is that both the hand and the brain in this case happen to be Pakistan. So, if we understand this particular aspect of this grave threat, then we will appreciate that there is no question of having any let-up so far as our measures for combating this militancy or insurgency, or any measures to win this proxy war, are concerned.

As has been rightly pointed out, this is a question which cuts across all the party lines for the simple reason that it really involves the sovereignty of our great nation, it involves the unity and integrity of our great nation and it in solves something which is basic, which is fundamental, to our society, to our Constitution, namely democracy and secularism. Each one of these elements is non-negotiable. And let it be made clear to the rest of the world. I am conscious of the pressure of the other world on us. But it should be made very clear by the Government to the rest of the world that we are not going to compromise on any one of the basic issues which I have mentioned.

Sir, one thing I may deal with in the beginning. It may be said that we are now taking the President's rule beyond a period of three years. But let it not be forgotten that we have extended it only to a period of four years. As against that, by a Constitutional amendment under sub-article (4) of Article 356,2nd proviso, in the case of Punjab, we have made it five years. And what is significant is that within five years, within that period, even earlier than that, we brought democracy back to rails in Punjab. And how did we bring it back to rails? By fighting militancy, by educating the people to realise that it does not help them to live in disturbed conditions of arms and violence. And I am quite sure that if we are determined, we will achieve the same results in the Valley. Of course, the Valley has many other, what shall I say, dimensions. I am sorry, 1 wanted to avoid saying, but I have to say that the way Pakistan is arming itself it has already acquired a nuclear capability the way it has added to its Air Force it is more than matching to our Air Force the Army, the Navy it is equal to our Navy the missiles and so many other things which they have got, it is not only a design of Pakistan, but it is a Pan Islamic design which we have to worry about. And it is in this context that I welcome the news which has appeared today in the newspapers saying that the USA is going to impose sanctions against both China and Pakistan for the sale of M—11 missiles.

SHRI G. G. SWELL (Meghalaya): Only some companies in China, not China as a whole.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: I know. I am happy because we see a trend which is just the beginning. Till today, despite the Pressler Amendment, the United States of America was turning a Nelson's eye to the nuclear bombs in the basement of Pakistan. I find that there is a realisation that India is a country which is wedded to peace, that it is a non-hegemonic country, that it has no expansionist designs at all and, therefore, it has not indulged in any proleferation of arms or even using its nuclear capability excepting for peaceful purposes. And I will tell you that whereas in real terms there has been no increase in our Defence budget, Pakistan allocated 34.6 per cent on Defence in its 1993-94 Budget out of a total current expenditure of 257,762 millions. I can go on giving figures. But this is not a Defence debate. Otherwise, I could go on giving the comparative positions, the comparative growths and find out how Pakistan is Irving out of its means--------1 do not know for what. I think, a time has come for those who have helped Pakistan, particularly the USA, to enforce the Pressler Amendment, to enforce other measures.

If they want peace, if the whole object is to reduce arms on our planet and if the whole object is to see that there is non-proliferation, then they must see that wherever there is proliferation, it must be stopped, and one country where there is maximum proliferation and for which the only target is our country, India, is Pakistan. Let us not make any mistake about it.

Let us be vigilant about it. Of course, I know we have the capability to teach them a lesson if need be. There is no question about our being weak in anyway. But their designs are not clear I would have myself suggested that we should go in for some kind of a no-war-treaty and it should be attempted with Pakistan, with China, and it may be very useful to ensure peace in this region. With China, things are really better but when one talks of peace, one talks about the region There is no threat from China at all China like India has not been a hegemonic country. There is no expansionism at all. But the point I am making is that even after entering into such a treaty, there is no guarantee that Pakislan would nol still continue in this proxy war because there is no war between the two countries. Therefore, I think, today the need of Ihe hour is-------and the House must be unanimous: it must speak with one voice—that ihe militancy must be totally brought tinder control and eliminated from the Valley..

1 do not believe in giving unlimited power to the army. Ultimately il cannot be forgotten that this is not a war. Therefor, you do not have somebody in uniform whom you can easily trace and kill What happens in militancy and insurgency and the proxy war is that all these militants mix up with the local population It has pained me; it has shocked me: it has alarmed me. But it is also one reason to take effective action on what was mentioned by the hon. Home Minister yesterday in the statement about infiltration of mercenaries on a large scale in the Valley from various parts of the world What happens is that they mix up with the local population and then you have this kind of a necessary operation of flushing out. You have to search and flush them nut. It is an operation which annoys a lot of civilian population. You know how we feel when we are searched. Today you saw how the Members were agitated because some Members were not allowed to come in their cars and because some cameras were installed here and there. Therefore, it is quite natural that innocent people get agitated when they are searched, their homes are searched and when they are Hushed out because many innocent people also suffer in the process. In this case I would request the hon. Home Minister to give definite directions for keeping in mind the basic theory' of the degree of proportionality No force should be used which is out of proportion to the needs of the situation. I think there is seme valid juslification for doing this. We do not want to be mthless or merciless but we definitely want all this militancy to end by use of reasonable force. and not unrestrictd use of force I would not stand for it. We are not really living in the days of Changez Khan.

Then, the issue of human rights remains some kind of a propaganda machine A reference was made to what happened at the global conference on human rights in Vienna and we had to fly Dr Farooq Abdullah to defend us. In fact, three-four days before we adjourned after the Budget Session I had mentioned, while speaking on the Kashmir issue, that in that global conference at Vienna, there would be an attempt to raise this issue of human rights It is a matter of regret that this issue was raised.

Then. 1 am glad to find that A. I. R. and Doordarshan have gone back there But those who have visited the valley I have visited Kashmir umpteen times would find that nobody listens to the All-India Radio, nor does anybody watch Doordarshan. They are all tuned to the Pakistan Radio and Pakistan Television This is partly because their programmes are far more superior to ours: their dramas, for instance; their *gazals* and their other musical programmes : Therefore, it is no use merely having them back, but you should also see that you improve the programmes. The quality should be such (hat the people would be forced to tune in to the All-India Radio or watch our Doordarshan.

I now come to the question of administration. I think there is a very wide gap between the general public and the administration. It always happens whenever the paramilitary forces take over, whenever the security forces are in charge. First of all. there is the general reason. Added to it. what happens is that the administration becomes callous, it becomes indifferent. I have not seen what the administration is doing. I am now suggesting some mechanism. In fact. I had suggested it several times earlier also. I do not want to repeat it. I had said that young Kashmiris should be brought and educated in other parts of the country It has not happened I say. if nothing else, you take them, at least, on school trips. You send them to Madras. You send them to Trivendrum. You send them to Agra. Let them see what India is. It will make a lot of difference. I would like the hon. Minister to find out how many school trips have been arranged in the last two years. What efforts were made by the administration to arrange such trips to other parts of the country so that the people of Kashmir have a feeling of oneness with the rest of the country?

I find that today, there is no machinery for people to air their grievances. Now. I am suggesting a small machinery. I .suggested that like the post-box. you keep some box at prominent places, called the grievance box. where people can put their petitions. If there is a medical van going around, apart from medicines and other things which the van may be equipped with, let there be also a grievance box there so that when people come, they can put their petitions. This kind of thing can be multiplied. It can he put even in a mobile postal van and what not.

Then, you should have some kind of an intercourse or *darbar* where people can come and talk to you. Consider this seriously. I would request the hon. Home Minister to consider this stiggestion seriously. Have a small committee of Members of Parliament from different parts of the country, a small committee, to oversee this particular aspect of grievances of the people. They will of course, first go through the petitions they receive. But they should also go there. It should be almost compulsory for this committee to go there three or four days in a month and find out the things for themselves. The feeling that we do nothing more than express our sympathy for the hardships of the people should go. Such a feeling can be removed when we go there. It is no use sending a learn once in a year. Then it becomes a gimmick. If it goes every month for three days, talks to people, listens to the grievances of the people and gives them the result by removing those grievances, it will go a very, very long way. Ultimately this is a battle between the bullet and the ballot. I have no doubt that the bullet will lose the battle and the ballot will succeed. I have no doubt at all, but it is a matter which will have to be pursued with a determination within the four corners of the protection of the human rights of the citizens, because if the people get a feeling that their basic rights are not safe in the hands of the Government, the road to democracy is going to be more difficult and more long. Therefore, I would say that the situation is difficult. I also realise that there is no easy or early solution for Kashmir, but thai is not to say that there is no light at the end of the tunnel. I am quite positive, as has been said by the hon. Minister in his speech that people are really fed up with this kind of life and we must use the services of the West and particularly of USA because we have so many things in common. Firstly we are combatting terrorists and the whole West is against terrorism, we are combatting the militants and the whole West is against militancy. We are the only people who have been successful in controlling the drugs and West is interested in this. We are interested in Controlling our arms and we are the foremost Nation in peace. If today the world is changing it is not changing into a unipolar world. Sic. lei the assure the hon. Home Minister that it may *he* felt as if the world is going to change into a Unipolar world, but it is not so. it is going into what I may call a democratic, non-violent and squal world. And for that democratic non-violent world nobody has belief credentials than India. Sir. this Kashmir can be the only Convenient way to build up the whole climate for a democratic, non-violent and equal world let India not lose this opportunity while solving *he problem of the valley while solving Ihe problem of insurgency, while bringing back 'femocracy on its path in the *valley*. and also to usher in this atmosphere of peace, non-violence and prosperity in the rest of the world

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी (उत्तर प्रदेश) शुक्रिया, सदरे मोहतरम। इस वक्त रियासते जम्मू और कश्मीर के हालात पर बहस का सिलसिला जारी है और हमारे दो फाजिल मेम्बराने पार्लियामेंट ने इस मसले पर कुछ रोशनी भी डाली है।

कश्मीर के हालात जिस तरह पहले थे, आज भी उन हालात में कोई पेशरफ्त सुधार की तरफ नहीं हुआ। कब्रिस्तान का पुरहोल सन्नाटा, चुनाव और सियासी अमल की गुफ्तगू, बेमिन्त मंजिल और बेमकसद हिकमते अमली कश्मीरी अवाम के दुख-दर्द को दूर नहीं कर सकते। हड़ताल, बंद, चक्का-जाम, सीनाकोबी और मातम कश्मीरियों की जिन्दगी का एक लाजिमी हिस्सा बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद कश्मीरियों की जबूहाली पर जब किसी रोज गुर्दिश के मतवाले रहम खाते हैं तो मामूल के मुताबिक दुकानें खुल जाती हैं, चहल-पहल श्रीनगर में शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है कि जिन्दगी मामूल पर आ गई है और कश्मीर एक पुरअमन वादी बनकर हिन्दुस्तान के उफक पर चमक रहा है। यह सूरत देख कर हमारे गवर्नर, हमारे आला अफसर और खुद हमारी मरकजी हुकूमत कभी असेंबली का चुनाव कराने और कभी सियासी अमल शुरू करने का एलान करती रहती है। मगर हुकूमत का यह हसीन सपना महज एक राकेट या एक भयानक बम के धमाके से चकनाचूर हो जाता है। आज ही गालिबन दूसरे हाउस में हमारी हुकूमत की तरफ से यह एलान हुआ है कि हालात मामूल पर आ रहे हैं। गवर्नमेन्ट रोज इस बात का एआदा करती है कि कश्मीर में हालात ठीक हो रहे हैं। चुनांचा आज भी दूसरे हाउस में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एलान किया है कि वहां के हालात सुधर रहे हैं। मगर हालात सुधरने का बेहतरीन नमूना आज ही के अखबार से जाहिर हो रहा है। कश्मीर के बड़े अफसर यानी डिविजनल कमिश्नर जनाब वजाहत हबीबुल्ला साहब, आई० ए० एस० जो कि हाल ही में दिल्ली से दोबारा

कश्मीर भेजे गए हैं डिप्टी कमिश्नर, बारामुला और सुपरिंटेंडेंट पुलिस, बारामुला के हमराह एक मीटिंग के सिलसिले में सोपोर . . . (व्यवधान) उनकी मीटिंग एस० डी० एम० के दफ़्तर में होनी थी। ज्यों ही टेरोरिस्टों को पता लगा उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ एस० डी० एम० के दफ़्तर का घेराव कर लिया। दो-एक बम फेंके और गोलियां चलाईं और बजाहत हबीबुल्ला साहब और उन्हीं के साथ-साथ दूसरे अफसरों को 5 घंटे तक उन्होंने अपने घेरे में रखा। अफसरों ने बी० एस० एफ० को मदद के लिए कहा मगर कोई नहीं आया और उन सब अफसरों की जानें खतरे में आ गईं। आखिर डिप्टी कमिश्नर ने सोपोर के किसी मुअज़्ज़िज़ शहरी को टेलीफोन किया कि टेरोरिस्टों से राबता पैदा करके घेराबंदी तुड़वा दी जाए और अफसरों की जान बचा ली जाए। आखिरकार वाइस चेयरमैन साहब, ऐसा ही हुआ और घेरा उठाया गया और अफसरान रात के 9.00 बजे श्रीनगर पहुंच गए। अगर गवर्नमेंट कहती है कि मिलिटरी ने घेरा उठाया मगर सच्चाई यह है कि उन अफसरों की जानें टेरिरिस्टों के ही घेरा उठने से बचीं जो कि सोपोर में राज और राज कर रहे हैं। मोहतरम सदर साहब, मैं यह बात सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूं, बल्कि आज ही का टाइम्स आफ़ इंडिया आप देख लीजिए, तफसील से ये सारी बातें उसमें दर्ज हैं। मैं यह चाहूंगा कि इस मामले में तहकीकात करवाई जाए। इन हालात में यह कहना कि हालात सुधर रहे हैं यह ख्वाब की दुनिया में रहने के मुतरादिफ है। दरअसल, खानियार का सानिहा 15-20 दिन का है आज वह हमें बतलाता है कि हालात कितने खराब हैं। सेक्योरिटी फोर्सेस एक घर में दाखिल होती है और उस सख्त के एक बच्चे को बेदर्दी के साथ कत्ल करती है और साथ ही साथ उस बच्चे के मां-बाप को भी मौत की गोद में सुला दिया जाता है। अफवाहों के शहर श्रीनगर पर आजकल डाइन छाई हुई है। तेज दातनी नाखून वाली डाइन, बुलेटप्रूफ जाकेट वाली डाइन, स्प्रिंग जूते वाली डाइन, यह डाइन बिल्कुल माडर्न डाइन है। किसी ने आज तक देखा नहीं, लेकिन अखबारात में डाइन की तस्वीर का पूरा खाका हुए बगैर, देखे बगैर, पकड़े बगैर डाइन को इस अंदाज से पेश किया जा रहा है जैसे कि पूरा कश्मीर डाइन की गिरफ़्त में है। जाननेवाले जानते हैं कि यह कश्मीरियों के सुकून को लूट लेने का एक हरबा है, उनको सड़कों पर लाने का एक हथियार है लेकिन हर कोई खामोश है क्योंकि खामोशी टूट गयी तो मुखबरी का जुर्म आयद होगा और इस जुर्म की सजा फांसी होगी। डाइन की अफवाह के पसेपरदा क्या अजाकार फरमा है, ये भी पढ़े-लिखे लोग जानते हैं, लेकिन निचली सतह के अफसरान बराबर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि बॉर्डर सेक्युरिटी फोर्स ने डाइन का रूप धारण किया है। इंतजामिया का खौफ तो है ही नहीं, कानूनी कार्यवाही की किसी को परवाह नहीं है, इसलिए सरकारी मुलाजिम आजादी के साथ अमनो-सुकून के आशियाने में आग लगा रहे हैं। सरकार, इंतजामिया के छोटे-बड़े अफसरों और मुलाजिमों ही ने दहशतजनदी को भी जिंदा कर रखा है क्योंकि दहशतगर्दी का माहौल लूट-खसोट, चोरी, कामचोरी, तनआसानी और गफलत का एक शाख्सेस बना हुआ है। गुजिश्ता वर्षों में सरकारी मुलाजिमों ने बेदर्दी से खजाने-आमिरा को लूटा है और उसमें उन्हें दहशतगर्दी की सरपरस्ती हासिल रही है जिनका न तो पाकिस्तान नवाजी के साथ कोई ताल्लुक है और न ही हिन्दुस्थान के साथ उनका कोई मोतबर नजरिया है। इसी तरह से गवर्नर साहब के बारे में भी जो रिपोर्ट आ रही हैं, वह बहुत दर्दनाक हैं। गवर्नर साहब भी आम-अवाम के साथ राब्ता रखते हुए शर्माते हैं। आम पब्लिक के साथ राब्ते के लिए वह सेक्रेटरी साहब का ताल्लुक पैदा करते हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब के जरिए ही अवाम की बातों को सुना जाता है और अवाम से ये वायदे किए जाते हैं कि आपके हालात पर हमारी निगाह है। डाका डालनेवाले, लड़कियों को अगवा करनेवाले, आम लोगों से पैसा बटोरनेवाले अपना धंधा तेजी के साथ चला रहे हैं कौमी दौलत बुरी तरह लूटी जा रही है और उन लुटेरों का ऐसा सिक्का चलता है कि अगर वह चाहे तो बीच सड़क पर भी मकान बना लेंगे, तामीर कर लेंगे और उनको कोई चैलेंज करनेवाला कानून वहां मौजूद नहीं है। *आम जनता इस जुल्म से तंग आ चुकी है।* कश्मीरी औरतों व मर्दों की गवर्नर, इंतजामिया और आला अफसरों के दफ़्तरों में लंबी कतारें लगी होती हैं। वह फरियाद करते हैं। सदर साहब, दरअसल उनकी यह फरियाद, उनकी यह बेकसी, कानून की दुहाई देकर अपने जानो-माल के तहफ़्फ़ुज की दुख-दर्द भरी आवाज सही मायनों में टेरेरिस्टस के खिलाफ और दहशतगर्दी के खिलाफ इहतजाज की एक आवाज है। गवर्नर हैं, इंतजामिया है, मगर जैसाकि मैंने पहले भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी के जरिए उन लोगों की परेशानियों पर गौर किया जाता है और चीफ सेक्रेटरी के बारे में आम शिकायत यह है कि उनके रिश्तेदार इस सूरते-हाल का पूरा फायदा उठा रहे हैं। आम शिकायत यह भी है कि इसका पूरा फायदा उठाकर टोस्ट के दोनों तरफ मक्खन लगाया जा रहा है। सेक्रेटरी साहब का एक बेटा सिविल सेक्रेटेरिएट में हुक्मरानी करता है। आला अफसरान उसके दरबार में हाजिर होते हैं और दूसरा बेटा जवाहर नगर के हाई-सेक्युरिटी जोन में ठेकेदारों और ताजिरों से नजराने वसूलता है। इन बड़े लोगों से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फरेंस के मेंबरों को शिकायत है कि सरकारी मुलाजिमों में दलाली का पेशा खूब नफ़ाबख्श बन चुका है। पढ़े-लिखे नौजवानों को सर्विस दिलाने की आड़ में कायदे और कानून की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं। दियानतदार अफसरों का कहत नहीं है, लेकिन उन्हें किनारे लगा दिया गया है और एक मंसूबे के तहत रियासत से हटाया गया है। आम कश्मीरी को भुखमरी का शिकार हम देखते हैं। यह भी हकीकत है कि सियासतदारों के रिश्तेदारों को कत्ल किया गया है, मगर कश्मीर में कौन बचा है जिसका कोई-न-कोई अजीज दहशतगर्दों या सेक्युरिटी फोर्सेस की कारस-परवरिश से न मारा गया हो? इन हालात में यह कहना कि कश्मीर में सियासती सूरते-हाल को जिंदा किया जाए, इलेक्शन करवाया जाए, सिवाय मजाक के और कोई दूसरी चीज नहीं है। यकीन जब उठ जाता है, एतमाद उठ जाता है तो करप्शन पैदा होता है। कश्मीर के नौजवानों में जो गुमराही आई है, उस गुमराही का एक बहुत बड़ा सबब हुकूमत की गफलत, लापरवाही और बदउनवान मुलाजिमों को उनकी बदउनवानी पर

सजा न देना है।

मरीजे इश्क पर रहमत खुदा की,
मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की।

कश्मीर को सुधारने के लिए, कश्मीर के हालात पर काबू पाने के लिए हमारी हुकूमत करोड़ों रुपया खर्च करती है। हर तरह का दल और बल कश्मीर में इस्तेमाल किया गया। मगर दल के इस्तेमाल का भी कोई फायदा दिखलाई नहीं देता और बल के इस्तेमाल का भी कोई फायदा दिखलाई नहीं देता। हम सोच रहे है इतनी ज्यादा फौज हमारी वहां लगी है, सिक्युरिटि फोर्सेस लगी है, पुलिस के कर्मचारी वहां काम कर रहे है, हमारी सी० आई० डी० वहां काम कर रही है, आवाम के साथ तआवुन की बातें भी की जा रही है, आखिर क्या बात है कि कश्मीर के हालात सुधरते हुए दिखलाई नहीं देते। कहीं न कहीं कोई कमी है, कहीं न कहीं कोई कमी है, कहीं न कहीं कोई अखलाक के तराजू पर हुकूमत पूरी उतरती हुई दिखलाई नहीं देती है। दुनिया भर के पैसे लगाए गए, मगर सड़कों की आज वही हालत है, स्कूलों में आज वही वीरानी है, हास्पीटलों में वही गम-व-अलम का माहौल है, पढ़े-लिखे लड़कों की आंखों में वही मायूसी का आलम है। आखिर कश्मीर पर यह सारी रकम लगाने के बाद भी यह रकम जाती कहां है? एक दरख्त भी लगाया जाए, उसको सींचा जाए तो वह दरख्त भी एकदम सायादार दरख्त बन जाता है। वहां करोड़ों और अरबों रुपए खर्च किए गए, मगर अमन-व-शान्ति का दरख्त कश्मीर की धरती पर उगता हुआ दिखलाई नहीं देता। बेपनाह पैसे खर्च किए गए, मगर इसके बावजूद कश्मीर की धरती पर हमें सही मुस्तकबिल का कोई पता मिलता दिखलाई नहीं देता। इसलिए कश्मीर में सियासी अमल शुरू करने की बात, इस इलेक्शन करवाने की बात चाहे हम अपने सियासी फायदे के तहत करते हों, मगर सच्चाई यह है कि जब तक अमन-व-अमान का माहौल नहीं पैदा होता, जब तक आवाम को यकीन में नहीं लिया जाता, जब तक अफसरान और आवाम खादिम-व-मखदूम का रिश्ता नहीं जुड़ता उस वक्त तक वहां के हालात पर काबू पाना निहायत ही मुश्किल है। पड़ोस के मुल्क की बात आई। मैं सफाई के साथ कहना चाहता हूं। कहना ही नहीं चाहता, मेरा जमीर इस बात को महसूस करता है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क की तरक्की और अमन का दुश्मन है। पाकिस्तान की बुनियाद ही हिन्दुस्तान की दुश्मनी पर उस्तवार की गई थी। पाकिस्तान से हमें इस बात की उम्मीद यूं भी नहीं रखनी चाहिए कि पाकिस्तान हमारे साथ खैर-सगाली का कोई हाथ बढ़ाएगा। पाकिस्तान दोस्ती के नाम पर हमारे साथ हमेशा दुश्मनी करता हुआ आया है। जब भी कमजोर पड़ा है उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जब भी ताकतवार हुआ है उसने हमारे मुल्क पर हमला किया है, हमारी सरहदों पर हमला किया है। पाकिस्तान ने बंगला देश का बदला लेने के लिए हिन्दुस्तान के अंदर एक ऐसी शोहरिश पैदा कर दी है। पंजाब की सरजमी पर हिन्दुस्तान की लहलहाती हुई फसल तबाही का जिम्मेदार पाकिस्तान है। कश्मीर की सरजमी पर झेलम जैसे दरिया से जो हिन्दू और मुसलमान एक साथ पानी पीते थे उन दोनों में नफरत का बाजार गर्म करने का जिम्मेदार पाकिस्तान है। न सिर्फ यहां पाकिस्तान ने कश्मीर, पंजाब की धरती पर नफरत के बीज बोए बल्कि उस नफरत के बीज ने इतना गलत असर हमारी हिन्दुस्तानी सोसायटी पर डाला है कि आज पूरे मुल्क में हिन्दू-मुस्लिम के मसालेहत, हिन्दू मुस्लिम की दोस्ती को शक की निगाह से देखा जाने लगा है। हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह के हालात पैदा हुए है, मैं उन हालात पर भी सफाई से बोलने का आदी हूं। हम अपने जमीर को टटोलते है, हमारे जमीर और खमीर के पैदाइश हिन्दुस्तानी है, इसलिए मुल्क की सलामती पर, मुल्क की सेहत पर जब भी कोई आंच आएगी तो हमारा उस तपिश में झुलस जाना एक फितरी अमल होगा।

आज हम इस हाऊस के जरिए पाकिस्तान से भी यह कहना चाहते है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में जो सरगरमियां जारी और सारी रखे हुए है, काश वह रकम जो हमारे मुल्क की तबाही के लिए वह लगा रहा है, काश वह हथियार जो हमारे मुल्क के लोगों के सीने गोलियों के जरिए उतारने के लिए टेररिस्टों के हाथों दे रहा है, काश वह अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपनी आवाम की खुशहाली के लिए उन्हीं पैसों को लगाता तो यह इंसानियत की खिदमत के लिए ज्यादा बेहतर होता। फिलहाल हम सरहद के पार की रियासत में दखल न देते हुए अपने मुल्क की सेहतमंद सियासत के लिए दर्दमन्दाना दिल रखते है। हमारे मोहतरम होम मिनिस्टर साहब यहां मौजूद है, हम उनसे यह अर्ज करना चाहेंगे कि बहुत ही खुदगर्जियों से ऊपर उठकर कश्मीर की सही सूरतेहाल का जायजा लिया जाना चाहिए। ज़ालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, मजलूमों की सच्ची ऐयानत की जाए, कश्मीर में जो औरतें अपनी मांग का सिंदूर उजड़वा चुकी हैं, जो बच्चे यतीम हो चुके है, जो फाकाकशी का शिकार है, जिन इंसानों की जिंदगी बेएतमादी की अलामत बन गई है वे इंसान हमारी पूंजी है, वही औरतें हिन्दुस्तानी है, वही बच्चे हिन्दुस्तान के शहरी है। इन बच्चों की जिंदगी को सेहतमंद बनाने के बाद ही हम कश्मीर में एक खूबसूरत सपना देख सकते है। पहाड़ों का नाम हिन्दुस्तान नहीं है, दरियाओं का नाम हिन्दुस्तान नहीं है, रेगिस्तानों का नाम हिन्दुस्तान नहीं है, हिन्दुस्तान के दरियाओं, रेगिस्तानों, पहाड़ों के साथ मोहब्बत करने वाले इंसानों का नाम हिन्दुस्तान है। आज जो इंसान तबाह किए जा रहे है, बर्बाद किए जा रहे हैं उन इंसानों की जिंदगी को बचाना, यह हम हिन्दुस्तानी शहरियों और जिम्मेदारों का फरीजा है। आज लगता है कि हम सबके सब अपने फरीज़े से सुबकदोश हो चुके है। कहीं न कहीं पानी मर रहा है जिसकी बुनियाद पर इतनी बड़ी उथल-पुथल मौजूद है। आज कश्मीर के फूल सूख चुके है, कश्मीर की कलियां बिखर चुकी है, कश्मीर का कहकहाजार किस की नजर हो चुका है। अगर हो सके तो कश्मीर की मुसर्रतें को आप फिर वापिस लाइए बजाए इलेक्शन और सलेक्शन की बात करने के बजाए अपनी पार्टी और अपनी हुकूमत के बरसरे इक्तेदार रहने की बात करने के, वहां के आम आवाम के मसायल पर तवज्जो दीजिए और यह जो पैसे दिए जा रहे है, उन पैसों का मुहासबा कीजिए। ये करोड़ो

रुपए गरीब आदमी की कमाई है, बड़ी ही मुसीबतों से गरीब उनको कमाता है, टैक्स देता है, गवर्नमेंट के पास खज़ाने की शक्ल में जमा होता है और अगर बेदर्दी के साथ ये पैसे बहाए जाते है, इन पैसों का कोई हिसाब नहीं होता है, रिश्वतखोरों को सजा नहीं मिलती है, टेरेरिस्टों का साथ देने वाले अफसरों को बर्खास्त नहीं किया जाता है, बेकसूर इंसानों को मारने वालों को सज़ा देने के बजाए अगर उन्हें तलाई तमगे दिए जाते है तो इससे शायद आपकी हुकूमत बच जाए मगर हिन्दुस्तान के मुस्तकबिल पर एक निशान लगेगा, हिन्दुस्तान की सेहतमंद अलामत को एक धक्का लगेगा। इसलिए मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बजट जरूर पास कीजिए, कश्मीरियों के हक में है यह बजट। यह पैसा वहां के गरीब आवाम पर लगना चाहिए उनकी समस्याओं पर लगना चाहिए। तानाशाह अफसरों से इन पैसों को बचाया जाए, एयर कंडीशनर के सामने बैठने वाले जो इन पैसों का बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करते है, उनपर कड़ी निगाह रखी जाए, बजाए इसके कि राज्य सभा में जासूस कैमरे लगाए जाएं। ये जासूस कैमरे अगर उन दलाल अफसरों के घरों में लगा दिए जाएं जो ज्यादा बेहतर होगा, ये जासूस कैमरे अगर उन रिश्वतखोर अफसरों के घरों में लगा दिए जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, जिन्होंने हिन्दुस्तान की मर्यादा को गारत कर दिया है, गंगा-जमनी तहज़ीब को बर्बाद कर दिया है। मैं उम्मीद नहीं करता आपकी जिम्मेदारी को समझते हुए यकीन रखता हूं कि आप इस पर हमदर्दी के साथ गौर करेंगे और इन पैसों का मुहासबा करेंगे कि बजट में जो पैसे आप दे रहे हैं, एक-एक पाई हिन्दुस्तान के लोगों की गाढ़ी कमाई की अमानत है। इस दौलत को जेहलम के दरिया में न बहने दीजिए, इस पैसे को रावी के पानी की तरह लोगों को इस्तेमाल न करने दीजिए बल्कि हकदार तक उसका हक पहुंचने दीजिए। जिस दिन आपने हकदार को हक दे दिया, फितने खत्म होंगे, जिस दिन आपने हकदार को उसका हक दे दिया, ताअस्सुब के बादल छटेंगे और नफरत का जो पानी बरस रहा है, वह पानी खत्म हो जाएगा।

इन्हीं जुमलों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए कश्मीर के लोगों के मुस्तकबिल की सही उम्मीद रखता हूं। खुदा हाफिज़।

مولانا عبید اللہ خاں اعظمی† (اتر پردیش): شکریہ۔ صدر محترم۔ اس وقت ریاست جموں اور کشمیر کے اخراجات پر بحث کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے دو معزز ممبران پارلیمنٹ نے اور مسئلہ پر کچھ روشنی بھی ڈالی ہے۔ کشمیر کے حالات جس طرح پہلے تھے آج بھی ان حالات میں کوئی پیش رفت سدھار کی طرف نہیں ہوا۔ قبرستان کا گھٹا ٹوپ سناٹا۔ چناؤ اور سیاسی عمل کی گفتگو بے سمت منزل اور بے مقصد حکمت عملی کشمیری عوام کے دکھ درد کو دور نہیں کر سکتے۔ ہڑتال۔ بند۔ چکا جام۔ سینہ کوبی اور ماتم کشمیریوں کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کشمیریوں کی زبوں حالی پر جب کسی روز حریت کے متوالے رحم کھاتے ہیں تو معمول کے مطابق دکانیں کھل جاتی ہیں چہل پہل سری نگر میں شروع ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ زندگی معمول پر آگئی ہے اور کشمیر ایک پر امن وادی بن کر ہندوستان کے افق پر چمک رہا ہے۔ یہ صورت دیکھ کر ہمارے گورنر۔ ہمارے اعلیٰ افسر اور خود ہماری مرکزی حکومت کبھی اسمبلی کا چناؤ کرانے اور کبھی سیاسی عمل شروع کرنے کا کام کرتی رہتی ہے مگر حکومت کا یہ حسین سپنا محض ایک راکٹ یا ایک بھیانک بم کے دھماکے سے چکنا چور ہو جاتا ہے آج ہی غالباً دوسرے ہاؤس میں ہماری حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ گورنمنٹ روز اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ کشمیر میں حالات ٹھیک ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آج بھی دوسرے ہاؤس

† [ ]Transliteration in Arabic Script

نو بجے سری نگر پہنچ گئے۔ اگرچہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ملٹری نے گھیرا اٹھایا مگر سچائی یہ ہے کہ ان افسروں کی جانیں ٹیررسٹوں کے ہی گھیرا اٹھانے سے بچیں۔ جو کہ سوپور میں راج اور تاج کر رہے ہیں۔ محترم صدر صاحب۔ میں یہ بات سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آج ہی کا ٹائمس آف انڈیا آپ دیکھ لیجیے۔ تفصیل سے یہ ساری باتیں اس میں درج ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس معاملہ کی تحقیق کروائی جائے۔ ان حالات میں یہ کہنا کہ حالات سدھر رہے ہیں یہ خواب کی دنیا میں رہنے کے مترادف ہے۔ دربیل۔ خانیساں کا سانحہ ۱۵۔۲۰ دن کا ہے

آج وہ ہمیں بتلاتا ہے کہ حالات کتنے خراب ہیں۔ سیکیورٹی فورسیز ایک گھر میں داخل ہوتی ہیں اور دس سال کے ایک بچے کو بیدردی کے ساتھ قتل کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس بچے کے ماں باپ کو بھی موت کی گود میں سلا دیا جاتا ہے۔ افواہوں کے شہر سری نگر پر آجکل ڈائن چھائی ہوئی ہے۔ تیز آہنی ناخن والی ڈائن۔ یہ ڈائن بالکل ماڈرن ڈائن ہے۔ کسی نے آج تک دیکھا نہیں۔ لیکن اخبارات میں ڈائن کی تصویر کا پورا خاکہ چھوئے بغیر۔ دیکھے بغیر پکڑے بغیر ڈائن کو اسی انداز سے پیش کیا جا رہا ہے جیسے کہ پورا کشمیر ڈائن کی گرفت میں ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ کشمیریوں

میں ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہاں کے حالات سدھر رہے ہیں۔ مگر حالات سدھرنے کا بہترین نمونہ آج ہی کے اخبار سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کشمیر کے بڑے افسر یعنی ڈویژنل کمشنر جناب وجاہت حبیب اللہ صاحب آئی۔ اے۔ ایس جو کہ حال ہی میں دلی سے دوبارہ کشمیر بھیجے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر بارہ مولہ اور سپرنٹنڈنٹ آف پولیس بارہ مولہ کے ہمراہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں سوپور ... "مداخلت"... ان کی میٹنگ ایس۔ ڈی۔ ایم۔ کے دفتر میں ہونی تھی جیوں ہی ٹیررسٹوں کو پتہ لگا انھوں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایس۔ ڈی۔ ایم۔ کے دفتر کا گھیراؤ کر لیا۔ دو ایک بم پھینکے اور گولیاں چلائیں اور وجاہت حبیب اللہ صاحب اور انہی کے ساتھ ساتھ دوسرے افسروں کو ۵ گھنٹے تک انھوں نے اپنے گھیرے میں رکھا۔ افسروں نے بی۔ ایس۔ ایف کو مدد کے لیے کہا۔ مگر کوئی نہیں آیا۔ اور ان سب افسروں کی جانیں خطرے میں آ گئیں۔ آخر ڈپٹی کمشنر نے سوپور کے کسی معزز شہری کو ٹیلیفون کیا کہ ٹیررسٹوں سے رابطہ پیدا کر کے گھیرا بندی تڑوا دی جائے۔ اور افسروں کی جان بچائی جائے۔ آخر کار وائس چیرمین صاحب۔ ایسا ہی ہوا اور گھیرا اٹھایا گیا اور افسران رات کے

آرہی ہے۔ وہ بہت دردناک ہے۔ گورنر صاحب بھی عام عوام کے ساتھ رابطہ رکھتے ہوئے شرماتے ہیں۔ عام پبلک کے ساتھ رابطے کے لیے وہ سکریٹری صاحب کا تعلق پیدا کرتے ہیں اور چیف سکریٹری صاحب کے ذریعے ہی عوام کی باتوں کو سنا جاتا ہے اور عوام سے یہ وعدے کئے جاتے ہیں کہ آپ کے حالات پر ہماری نگاہ ہے۔ ڈاکہ ڈالنے والے لڑکیوں کو اغوا کرنے والے۔ عام لوگوں سے پیسہ بٹورنے والے اپنا دھندا تیزی کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ قومی دولت بری طرح لوٹی جا رہی ہے۔ اور ان لیڈروں کا ایسا سکہ چلتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو بیچ سڑک پر بھی مکان بنا لیں گے۔ تعمیر کریں گے۔ اور ان کو کوئی چیلنج کرنے والا قانون وہاں موجود نہیں ہے۔ عام جنتا اس ظلم سے تنگ آچکی ہے۔ کشمیری عورتوں و مردوں کی گورنر انتظامیہ۔ اعلیٰ افسروں کے دفتروں میں لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ وہ فریاد کرتے ہیں۔ صدر صاحب۔ دراصل ان کی یہ فریاد۔ ان کی یہ بے کسی قانون کی دہائی دیکر اپنے جان و مال کے تحفظ کی درد بھری آواز صحیح معنوں میں ٹیرورسٹوں کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف احتجاج کی ایک آواز ہے۔ گورنر ہے۔ انتظامیہ ہے۔ مگر کے سکون کو لوٹ لینے کا ایک حربہ ہے۔ ان کو سڑکوں پر لانے کا ایک ہتھیار ہے۔ لیکن ہر کوئی خاموش ہے۔ کیونکہ خاموشی ٹوٹ گئی تو مخبری کا جرم عائد ہوگا۔ اور اس جرم کی سزا پھانسی ہوگی۔ ڈائن کی افواہ کے پس پردہ کیا جذبہ کار فرما ہے۔ یہ بھی پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں لیکن نچلی سطح کے اہلکار برابر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ بارڈر سیکیورٹی فورس نے ڈائن کا روپ دھارن کیا ہے۔ انتظامیہ کا خوف تو ہے ہی نہیں قانونی کارروائی کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے سرکاری ملازمین آزادی کے ساتھ امن و سکون کے شامیانے میں آگ لگا رہے ہیں۔ سرکار۔ انتظامیہ کے چھوٹے بڑے افسروں اور ملازموں ہی نے دہشت پسندی کو بھی زندہ کر رکھا ہے۔ کیونکہ دہشت گردی کا ماحول لوٹ کھسوٹ چوری۔ کا نچوری۔ تن آسانی اور غفلت کا ایک لائیسنس بنا ہوا ہے۔ گزشتہ برسوں میں سرکاری ملازموں نے بیدردی سے خزانۂ عامرہ کو لوٹا ہے اور اس میں انھیں دہشت پسندوں کی سرپرستی حاصل رہی ہے۔ جن کا نہ تو پاکستان نوازی کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ہندوستان کے ساتھ ان کا کوئی معتبر نظریہ ہے اسی طرح سے گورنر صاحب کے بارے میں بھی جو رپورٹ

گیا ہوں۔ ان حالات میں یہ کہنا کہ کشمیر میں سیاسی صورتحال کو زندہ کیا جائے۔ الیکشن کروایا جائے۔ سوائے مذاق کے اور کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یقین جب اٹھ جاتا ہے۔ اعتماد جب اٹھ جاتا ہے۔ تو کرپشن پیدا ہوتا ہے۔ کشمیر کے نوجوانوں میں جو گمراہی آئی ہے۔ اس گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب حکومت کی غفلت۔ لاپرواہی اور بدعنوان ملازموں کو ان کی بدعنوانی پر سزا نہ دینا ہے۔

مریض عشق پر رحمت خدا کی
مرض بڑھتا ہی گیا جیوں جیوں دوا کی

کشمیر کو سدھارنے کے لیے۔ کشمیر کے حالات پر قابو پانے کے لیے ہماری حکومت کروڑوں، کروڑوں روپیے خرچ کرتی ہے۔ ہر طرح کا دل اور بل کشمیر میں استعمال کیا گیا۔ مگر دل کے استعمال کا کوئی فائدہ دکھلائی نہیں دیتا اور بل کے استعمال کا بھی کوئی فائدہ دکھلائی نہیں دیتا۔ ہم سوچ رہے ہیں۔ اتنی زیادہ فوج ہماری وہاں لگی ہوئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز لگی ہیں۔ پولیس کے کر مچاری وہاں کام کر رہے ہیں۔ ہماری سی۔ آئی۔ ڈی۔ وہاں کام کر رہی ہے۔ عوام کے ساتھ تعاون کی باتیں بھی کی جارہی ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ کشمیر کے حالات سدھرتے ہوئے دکھلائی نہیں دیتے۔ کہیں نہ کہیں کوئی کچھ ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے۔ کہیں نہ

جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ چیف سکریٹری کے ذریعے ان لوگوں کی پریشانیوں پر غور کیا جاتا ہے۔ اور چیف سکریٹری کے بارے میں عام شکایت یہ ہے کہ ان کے رشتہ دار اس صورت حال کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عام شکایت یہ بھی ہے کہ اس کا پورا فائدہ اٹھا کر ٹورسٹ کے دونوں طرف مکھن لگایا جا رہا ہے۔ سکریٹری صاحب کا ایک بیٹا سول سکریٹریٹ میں حکمرانی کرتا ہے۔ اعلیٰ افسران اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور دوسرا بیٹا جواہر نگر کے ہائی سیکیورٹی زون میں ٹھیکیداروں اور تاجروں سے نذرانے وصول کرتا ہے۔ ان بڑے لوگوں سے کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے ممبروں کو شکایت ہے کہ سرکاری ملازمین میں دلالی کا پیسہ خوب نفع بخش بن چکا ہے۔ پڑھے لکھے نوجوانوں کو سروس دلانے کی آڑ میں قاعدے قانون کی دھجیاں اڑائی جارہی ہیں۔ دیانت دار افسروں کا قحط نہیں ہے۔ لیکن انھیں کنارے لگا دیا گیا ہے اور ایک منصوبے کے تحت ریاست سے ہٹایا گیا ہے۔ عام کشمیری کو بھکرداؤ کا شکار ہم دیکھتے ہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ سیاست داروں کے رشتہ داروں کو قتل کیا گیا ہے۔ مگر کشمیر میں کون بچا ہے جس کا کوئی نہ کوئی عزیز دہشت گردوں یا سیکیورٹی فورسز کی کراس فائرنگ سے نہ مارا

کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہنا ہی نہیں چاہتا۔ میرا ضمیر اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ پاکستان ہمارے ملک کی ازلی اور ابدی کا دشمن پاکستان کی بنیاد ہی ہندوستان کی دشمنی پر استوار کی گئی تھی۔ پاکستان سے ہمیں اس بات کی امید یوں بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ پاکستان ہمارے ساتھ خیر سگالی کا کوئی ہاتھ بڑھائیگا۔ پاکستان دوستی کے نام پر ہمارے ساتھ ہمیشہ دشمنی کرتا ہوا آیا ہے۔ جب بھی کمزور پڑا ہے اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جب بھی طاقتور ہوا ہے اس نے ہمارے ملک پر حملہ کیا ہے۔ ہماری سرحدوں پر حملہ کیا ہے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کا بدلہ لینے کے لیے ہندوستان کے اندر ایک ایسی شورش پیدا کر دی ہے۔ پنجاب کی سرزمین پر ہندوستان کی لہلہاتی ہوئی فصل کی تباہی کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ کشمیر کی سرزمین پر جھیلم جیسے دریا سے جو ہندو اور مسلمان ایک ساتھ پانی پیتے تھے۔ ان دونوں میں نفرت کا بازار گرم کرنے کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ نہ صرف یہاں پاکستان نے کشمیر۔ پنجاب کی دھرتی پر نفرت کے بیج بوئے بلکہ اس نفرت کے بیج نے اتنا غلط اثر ہماری ہندوستانی سوسائٹی پر ڈالا ہے۔ کہ آج پورے ملک میں ہندو مسلم کے مصالحت۔ ہندو مسلم کی دوستی کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا ہے۔

کہیں کوئی اخلاقی کے ترازو پر حکومت پوری اترتی ہوئی دکھلائی نہیں دیتی ہے۔ دنیا بھر کے پیسے لگائے گئے۔ مگر سڑکوں کی آج وہی حالت ہے۔ اسکولوں میں آج وہی ویرانی ہے۔ ہاسپٹلوں میں وہی غم و الم کا ماحول ہے۔ پڑھے لکھے لڑکوں کی آنکھوں میں وہی مایوسی کا عالم ہے۔ آخر کشمیر پر یہ ساری رقم لگانے کے بعد بھی یہ رقم جاتی کہاں ہے۔ ایک درخت بھی لگایا جائے اس کو سینچا جائے تو وہ درخت بھی ایک دم سایہ دار درخت بن جاتا ہے۔ وہاں کروڑوں اربوں روپے خرچ کئے گئے۔ مگر امن و شانتی کا درخت کشمیر کی دھرتی پر اُگتا ہوا دکھلائی نہیں دیتا۔ بے پناہ پیسے خرچ کیے گئے۔ مگر اس کے باوجود کشمیر کی دھرتی پر ہمیں صحیح مستقبل کا کوئی پتہ ملتا دکھلائی نہیں دیتا۔ اس لیے کشمیر میں سیاسی عمل شروع کرنے کی بات۔ اور الیکشن کروانے کی بات چاہے ہم اپنے سیاسی فائدوں کے تحت کرتے ہوں۔ مگر سچائی یہ ہے کہ جب تک امن و امان کا ماحول نہیں پیدا ہوتا۔ جب تک عوام کو یقین میں نہیں لیا جاتا۔ جب تک افسران اور عوام سے خادم اور مخدوم کا رشتہ نہیں جڑتا اس وقت تک وہاں کے حالات پر قابو پانا نہایت مشکل کام ہے۔

پڑوس کے ملک کی بات آئی۔ میں افغانی

پہنچا جائے۔ مظالموں کی سچی اعانت کی جائے کشمیر میں جو عورتیں اپنی مانگ کا سندور اجڑوا چکی ہیں۔ جو بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ جو فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ جن انسانوں کی زندگی بے اعتمادی کی علامت بن گئی ہے۔ وہ انسان ہماری پونجی ہیں وہی عورتیں ہندوستانی ہیں وہی بچے ہندوستان کے شہری ہیں۔ ان بچوں کی زندگی کو صحت مند بنانے کے بعد ہی ہم کشمیر میں ایک خوبصورت سپنا دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں کا نام ہندوستان نہیں ہے۔ ہندوستان کے دریاؤں کا نام ہندوستان نہیں ہے۔ ریگستانوں کا نام ہندوستان نہیں ہے۔ ہندوستان کے دریاؤں۔ ریگستانوں۔ پہاڑوں کے ساتھ محبت کرنے والے انسانوں کا نام ہندوستان ہے۔ آج جو انسان تباہ کیے جا رہے ہیں۔ برباد کیے جا رہے ہیں۔ ان انسانوں کی زندگی کو بچانا۔ یہ ہم ہندوستانی شہریوں اور ذمہ داروں کا فریضہ ہے۔ آج لگتا ہے کہ ہم سب کے سب اپنے فریضے سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے۔ جس کی بنیاد پر اتنی بڑی اتھل پتھل موجود ہے۔ آج کشمیر کے پھول سوکھ چکے ہیں۔ کشمیر کی کلیاں بکھر چکی ہیں۔ کشمیر کا قہقہہ زار قبر کی نذر ہو چکا ہے۔ اگر ہو سکے تو کشمیر کی مسرتوں کو آپ پھر واپس لائیے۔ بجائے الیکشن اور سلیکشن کی بات کرنے کے۔ بجائے ہمارے ملک کے اندر جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ میں ان حالات پر بھی صفائی سے بول لینے کا عادی ہوں۔ ہم اپنے ضمیر کو ٹٹولتے ہیں ہمارے ضمیر اور ضمیر کے پیدائش ہندوستانی ہے اس لیے ملک کی سلامتی پر ملک کی صحت پر جب بھی کوئی آنچ آئے گی۔ تو ہمارا اس تپش میں جھلسی جانا ایک فطری عمل ہوگا۔

آج ہم اس ہاؤس کے ذریعے پاکستان سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے ملک میں جو سرگرمیاں جاری اور ساری رکھے ہوئے ہے کاش وہ رقم جو ہمارے ملک کی تباہی کے لیے وہ لگا رہا ہے۔ کاش وہ ہتھیار جو ہمارے ملک کے لوگوں کے سینے گولیوں کے ذریعے اتارنے کے لیے ٹیررسٹوں کے ہاتھوں میں دے رہا ہے۔ کاش وہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے۔ اپنی عوام کی خوشحالی کے لیے ان ہی پیسوں کو لگاتا تو یہ انسانیت کی خدمت کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔

فی الحال ہم سرحد کے پار کی سیاست میں دخل نہ دیتے ہوئے اپنے ملک کی صحت مند سیاست کے لیے درد مندانہ دل رکھتے ہیں۔ ہمارے محترم ہوم منسٹر صاحب یہاں موجود ہیں۔ ہم ان سے یہ عرض کرنا چاہیں گے۔ کہ بہت ہی خود غرضیوں سے اوپر اٹھ کر کشمیر کی صحیح صورتحال کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ ظالم کو کیفر کردار تک

جو ان پیسوں کا بیدردی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ان پر کڑی نگاہ رکھی جائے۔ بجائے اس کے کہ راجیو سبھا میں جاسوسی کیمرے لگائے جائیں۔ یہ جاسوسی کیمرے اگر ان دلال افسروں کے گھروں میں لگا دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ جاسوسی کیمرے اگر ان رشوت خور افسروں کے گھروں میں لگا دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جنہوں نے ہندوستان کی مریادا کو غارت کر دیا ہے۔ گنگا جمنی تہذیب کو برباد کر دیا ہے۔ میں امید نہیں بلکہ آپ کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یقین رکھتا ہوں کہ آپ اس پر ہمدردی کے ساتھ غور کریں گے۔ اور ان پیسوں کا محاسبہ کریں گے کہ بجٹ میں جو پیسے آپ دے رہے ہیں ایک ایک پائی ہندوستان کے لوگوں کی کڑی کمائی کی امانت ہے۔ اس دولت کو جھیلم کے درمیان میں نہ بہنے دیا جائے۔ اس پیسے کو راوی کے پانی کی طرح لوگوں کو استعمال نہ کرنے دیجیے۔ بلکہ حقدار تک اس کا حق پہنچنے دیجیے۔ جس دن آپ نے حقدار کو اس کا حق دے دیا۔ تعصب کے بادل چھٹیں گے۔ اور نفرت کا جو پانی برس رہا ہے۔ وہ پانی ختم ہو جائے گا۔

ان ہی جملوں کے ساتھ میں اس بل کا سمرتھن کرتے ہوئے۔ کشمیر کے لوگوں کے مستقبل کی صبح امید رکھتا ہوں۔ خدا حافظ۔

اپنی پارٹی اور اپنی حکومت کے برسر اقتدار رہنے کی بات کرنے کے۔ وہاں کے عام عوام کے مسائل پر توجہ دیجیے۔ اور وہاں جو پیسے دیے جا رہے ہیں۔ ان پیسوں کا محاسبہ دیجیے۔ یہ کروڑوں روپے غریب آدمی کی کمائی ہے۔ بڑی ہی مصیبتوں سے غریب ان کو کماتا ہے۔ ٹیکس دیتا ہے۔ گورنمنٹ کے پاس خزانے کی شکل میں جمع ہوتا ہے۔ اور اگر بیدردی کے ساتھ یہ پیسے بہائے جاتے ہیں ان پیسوں کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے۔ رشوت خوروں کو سزا نہیں ملتی ہے۔

ٹیرورسٹوں کے ساتھ دینے والے افسروں کو برخاست نہیں کیا جاتا ہے۔ سیکولر انسانوں کو مارنے والوں کو سزا دینے کے بجائے اگر انھیں طلائی تمغے دیے جاتے ہیں تو اس سے شاید آپ کی حکومت بچ جائیگی مگر ہندوستان کے مستقبل پر ایک نشان لگے گا۔ ہندوستان کی صحت مند علامت کو ایک دھکا لگے گا۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بجٹ ضرور پاس کیجیے۔ کشمیریوں کے حق میں ہے یہ بجٹ۔ یہ پیسہ وہاں کے غریب عوام پر لگنا چاہیے۔ ان کی سمسیاؤں پر لگنا چاہیے۔ تاناشاہ افسروں سے ان پیسوں کو بچایا جائے۔ لائر کنڈیشن کے سامنے بیٹھنے والے لوگ

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman. Sir. thank you for giving me this opportunity to speak on the Statutory Resolution moved by the Hon. Home Minister for extending President's rule in Jammu and Kashmir and the Jammu and Kashmir Appropriation (No. 2) Bill, 1993 moved by the hon. Minister of State for Finance. Sir, the Jammu and Kashmir issue is a vexed issue. We have been discussing that issue—extension of President's rule and Budget—for more than four years in this House. We had an elected Government there. But because of the deteriorating law and order situation in Jammu and Kashmir and the increasing militant activities, the Government of India had to impose President's rule there. Sir, it is not a problem created from within our country. It is known to everybody that it lis Pakistan, which is our neighbour, that has been engineering, aiding and abetting terrorist activities in the border areas of Jammu and Kashmir. They are spreading to Punjab also. But in Punjab, we were able to contain the situation and elections were held and the new Government is tackling militancy in Punjab. As far as Jammu and Kashmir is concerned, in spite of the several assurances given by the hon. Minister for Home Affairs that elections will be held and a popular Government will be installed there, we have been coming to the House forgetting extension of President's rule. I was also asking the question why elections could not be held there. A delegation of Members of parliament visited Srinagar recently. The delegation consisted of leaders from various political parties. After seeing the conditions there, the delegates themselves came back and said that the situation was not conducive for holding elections in Jammu and Kashmir because militancy was on the rise and though the local administration, the police and the military were trying their level best to contain militancy, with the active connivance of Pakistan, militants were creating law and order problems there, killing innocent people and terrorising the people who were living in border areas. I would like to submit here that among the people who are living in rural areas, boys in the age group of 14-15 years are being taken away in groups by the militant organisations there and they are given training in Pakistan. After that, with weapons, they are sent back to India for creating law and order problems. Now, the situation is slowly changing. I say this because earlier, information about militants was furnished in Jammu and Kashmir by the people themselves. Now, the militants who have been captured by the military and the security forces are giving the information about the hide-outs of militants, their operations, the involvement of Pakistan, the training camps and about other militant activities. The military and the para-military forces in the State have fanned out up to border areas and they have arrested hundreds of militants. There is now fear in the mind of militant organisations that there will be no more public support for them in Jammu and Kashmir. Now the situation has changed there. The militants were getting support in Jammu and Kashmir earlier. People, because of the fear in their mind that the militants would kill them, had been giving them protection. The militants had been pressurising the people of that area. They were terrorising them. Especially, they were telling, the ladies there that they should not go to films outside, they should not go to hotels and when they go outside, they should go with full *purdah.* This was the direction given by the militant organisations to the womanfolk and if they were found violating that direction, they used to be killed. Therefore, the women have totally ignored the militants. A situation has now come that the militants are being identified and shown to the military and the BSF people. Now: the militants have started realising that their life is not secure because the prople are not cooperating with them. As far as Pakistan is concerned, the hon. Home Minister said that several times, the Government of India had written to the Government of Pakistan about the subversive activities being carried out by the militant organisations with the active help and support of I. S. I. in Jammu and Kashmir. The Government of India has given the proof also. But in spite of that, Pakistan has not changed its attitude. In the OIC and also in the U. N., Pakistan has been raising the issue of Jammu and Kashmir by totally ignoring the Simla Agreement. Pakistan has been saving that Jammu and Kashmir is an integral part of Pakistan. Sir, in this respect, the stand of the Government of India is very clear. According to the Simla Agreement Jammu and Kashmir is an integral part of our country. We have been telling this thing in the U. N. forum as well as in the other international forums. But in the name of violation of human rights, Pakistan has been spreading a false propaganda against the Government of India saying that in India, especially in Jammu and Kashmir, the people belonging to a particular community, are being killed indiscriminately by the security forces. The Government of India had taken a strong objection to

such utterances of Pakistan. The hon. Home Minister has given a clear reply to them. But in spite of that, they have been pursuing this policy. It is not that Pakistan is against India with regard to Jammu and Kashmir only but because of certain political reasons also, Pakistan wants to keep this issue alive for their survival. Therefore, this is a very ticklish issue. The issue of Jammu and Kashmir is not like that of Punjab. In Punjab, only one or two militant organisations have been operating. But as far as Jammu and Kashmir is concerned, the militant organisations, with the active connivance of Pakistan, have been creating law and order problem. The hon. Home Minister visited Jammu and Kashmir and he had the first hand information about the whole thing. I would like to submit that the Government of India should take a hard line with regard to this problem. Unless the Government of India takes a firm stand with regard to militants, it will be very difficult to curb militancy or eliminate terrorism in Jammu and Kashmir. In the changed circumstances, even the Governor said that the situation has changed and it would be possible to hold elections in Jammu and Kashmir. The hon. Minister of State for Home Affairs also gave that assurance. Therefore, Sir. I would like to know what steps have been taken to start the political process. As on today, not even a fraction of this process has started. The administration is being run by the bureaucrats in Jammu and Kashmir, at the moment. The people of the State have no forum to ventilate their grievances. They cannot approach the Governor they cannot go to the Advisors; they cannot go and tell their problems to the officers. In order to solve their problems, the political process should be started. Only through a political process, their problems could be solved. A military solution is not the ultimate solution to minimise militancy in Jammu and Kashmir. The Home Minister also appointed the Advisory'Committee. I do not know how many times they have met I would like to know when the political process is going to be started.

Then I come to tourism. I came to know that the Government of Jammu and Kashmir has decided to develop some tourist spots for the people who go there in some parts of the Kashmir Valley. I would like to know about the development of tourism. I would like to know whet steps you have taken in this regard to see that normalcy is restored in that area and the people from other regions can go there and they can also interact with the people of Jammu and Kashmir. Apart from that recently an unfortunate incident of mass killing of about 16 people had taken place in Doda District. Sixteen bus passengers lost their lives. Earlier it was a peaceful area. Now in the border areas of Jammu region the militancy has started. It is a very serious thing. That has also to be curbed. In the Jammu and Kashmir region which was a peaceful region and where the people belonging to all religions are living peacefully, the militants have started their nefarious designs. That should also be aken care of. Now that the situation is coming to normal, the people are cooperating with the Government, Ihe militancy is under control, the militancy is slowly coming down and in some areas it has been eliminated, I would suggest to the hon. Home Minister that he should call those militants who are willing to lay down their arms and abide by the constitution. He should discuss with them and try to bring them in to the mainstream. That is also a proposal which can be considered. It will help in eliminating militancy in that area. While supporting the Bill and also the Proclamation moved by the hon. Home Minister, I expect that he would not come after six months with another proposal about extending the President's rule. I think he will take all possible steps for restoring normalcy in Jammu and Kashmir. Thank You.

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल) : मुहतरिम वाइस-चेयरमैन साहब, छः महीने के बाद मरकजी हुकूमत फिर अपने चेहरे पर नाकामियों की राख मल कर पैसा मांगने के लिए चली आई है । छः महीने पहले जो कुछ कहा गया था और उससे जो उम्मीद बंधी थी उस पर फिर एक बार पानी फिर गया । काश्मीर का मसला और उलझ गया है । छः महीने पहले जब इस एवान में बहस हुई थी तो कई मेम्बरों ने यह सलाह दी थी कि काश्मीरी अवाम के दिल में उतरने की जरूरत है और यह मसला सेक्योरिटी फोर्सेज के जरिये हल होने वाला नहीं है । लेकिन इस बीच में कोई मुसब्बत कदम नहीं उठाया गया । काश्मीर में दो ताकतें काम कर रही हैं । एक तो वह जो काश्मीर को हिन्दुस्तान से अलग करना चाहती है और दूसरी वह ताकत है जो काश्मीर को हिन्दुस्तान में रखना चाहती है और काश्मीरी अवाम के जो हकूकी मसायल हैं उनको हल करना चाहती हैं । इसलिए हुकूमत को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जो ताकत काश्मीर को हिन्दुस्तान से अलग करना चाहती है वह ताकत अलग-थलग हो जाए । जो लोग काश्मीर को हिन्दुस्तान में रखना चाहते हैं उनके कदम मजबूत हों । उनका एतमाद हासिल हो । तो हुआ क्या ? अब जमाते इस्लामी खुल्लमखुल्ला काश्मीर का पाकिस्तान से इलहाक चाहती है । जाहिर है कि इसके बारे में रवैया एक किस्म का होगा । एक और तनजीम है जिसका नाम जम्मू-काश्मीर महाजे आजादी है यानी जे० के० एल० एफ० । वह यह चाहते हैं कि काश्मीर के अवाम को अख्तियारात मिले, उनके

मसायल हल हों । यह बिलकुल हकूकी बात है । इसलिए हमारी हुकूमत ने क्या कोई ऐसी कोशिश की है कि जम्मू-काश्मीर मझबे आजादी के साथ रास्ता कायम किया जाय, उनको बातचीत में लिया जाय ? ऐसी कोई कोशिश देखने में नहीं आती । हुकूमत 23 अरब 41 करोड़ 23 लाख 8 हजार रुपये मांग रही है । हम लोगों के सामने इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि यह पैसा देने की राय दें और सदर राज की तौसी का भी एलान करें क्योंकि यह बात सही है कि इलेक्शन कराने की हालत अभी भी नहीं है । अभी कुछ दिन पहले जो बस पैसेंजरों का कत्ल किया गया उससे बहुत सूरते हाल वाजे होती है । मैं जो लोग कत्ल किये गये हैं उनके कुरसा से इजहारे हमदर्दी करता हूं और जिन्होंने यह काम किया है उनकी मजम्मत करता हूं । एक फिरके के लोगों को मारा गया और इस तरह से दहशतगर्दी का जवाब दहशतगर्दी से देने की कोशिश की गयी । जो मारे गये वे मासूम थे, वे बेगुनाह थे, उनका कोई कसूर नहीं था । जुल्म बहरहाल जुल्म है, चाहे किसी फिरके के ऊपर हो और मुल्क के किसी हिस्से में हो । उसकी बिला इम्तियाद मजम्मत होनी चाहिये । जनाब, मैं जो कुछ कहना चाहता था वह यह है कि कश्मीर की हालत को बिगाड़ने में पाकिस्तान का हाथ है । इसके बारे में दो राय नहीं हो सकती । लेकिन पाकिस्तान यह खुद अपनी ताकत के बल पर नहीं कर रहा है । उसके पीछे अमेरिकन साम्राज्यवाद की पुश्तपनाही है । हमारी हुकूमत अमेरिका के पास बार बार दौड़ कर जा रही है कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को टैरोरिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए । और अमेरिका क्या कर रहा है ? अमेरिका उस को हकूकी ईसानी सवाल बना रहा है जिसकी हमें फिर मुदाफेअत करना पड़ती है । मरकजी हुकूमत अगर यह समझती है कि कश्मीर के बारे में अमेरिका हिन्दुस्तान की मदद करेगा तो वह गलतफहमी में मुब्तिला है । अगर यह गलतफहमी किसी कद्र दूर हो जाय तो उतना ही अच्छा है । अमेरिकी साम्राज्यवादी सिर्फ इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में दुश्मनी बढ़ती जाय और उसके लिये कश्मीर एक मौजू बना रहे । इसके जरिये वह अपना काम बनाना चाहता है । इस बात को हुकूमत अगर समझती भी है तो साफ लफ्जों में कहती नहीं है क्योंकि हुकूमत को हमेशा इस बात का डर है कि अगर वह अमेरिका पर तनकीद करेगा तो आलमी बैंक और मानेटरी फंड से पैसा नहीं मिलेगा । यह उनकी कोशिश है और इस तरह से यह मामला बिगड़ रहा है, उलझ रहा है । कश्मीर की अवाम दो तरह के जुल्मों का शिकार है । एक तरफ तो दहशतपसंद उनको कत्ल कर रहे हैं और दूसरी तरफ सेक्योरिटी फोर्सेस जवाबी कार्यवाही कर रही है । इसका शिकार भी वही लोग होते हैं । अगर वहां कोई वाकया होता है, कोई हादसा होता है तो उस वक्त सेक्योरिटी फोर्सेस का कहीं पता नहीं चलता । लोग मर जाते हैं, घरों को आग लगाकर जला दिया जाता है, उनको लूटा जाता है, कत्ल हो जाते है, आगजनी हो जाती है तब सेक्योरिटी फोर्सेस के लोग पहुंचते हैं और जब वे पहुंचते हैं तो फिर वह जब अपनी कार्रवाई करते हैं तो उसके शिकार भी ये मासूम लोग होते हैं । जो कसूरवार हैं वे कभी कभार ही गिरफ्त में आते हैं, ज्यादातर नहीं आते हैं । इसलिये कश्मीर की अवाम के दिल में यह जो फोर्स, बार्डर सेक्योरिटी फोर्स और सी० आर० पी० एफ०— जो ये पैरा मिलिटरी के लोग हैं ये सारे लोग खराब नहीं हैं, यह बात कोई नहीं कहेगा । लेकिन कुछ लोग हैं जो गलत काम करते हैं, चाहे जानबूझकर कर रहे हों या अनजाने में कर रहे हों । लेकिन आम लोगों की निगाह में जितने भी वर्दीपोश हैं वे सब जालिम हो गये हैं । जब किसी मामले में इम्प्रेशन बिगड़ जाता है तो फिर उसको ठीक करने में बड़ा वक्त लगता है । इसलिये हुकूमत को जो कदम उठाना चाहिये वह यह है कि अगर लोगों की शिकायतें हैं तो यह सोचे कि वे उन शिकायतों को लेकर कहां जाय । उस तरफ के एक मेंबरान ने इसका जिक्र किया है । वहां फरियाद की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई दरवाजा खुला नहीं है । हम लोगों ने बहुत पहले कहा था कि एक मसावर्ती कमेटी बनायी जाय, पूरे जम्मू और कश्मीर की सतह पर और नीचे की सतह पर भी ताकि गांव के लोग उसके पास पहुंच सकें और वे अपनी तकलीफों को बगैर किसी खौफ के बयान कर सकें और फिर उन तकलीफों को दूर करने के लिये कदम उठाये जाय । अगर यह नहीं हुआ तो फिर मेरे हिसाब से बंदूक के जोर से कश्मीर में अमन बहाल नहीं कराया जा सकता है, हालात मामूल पर नहीं लाये जा सकते हैं । अभी मौलाना ने एक वाकयात का बयान किया कि स्कूल में पढ़ने वाले दस साल के बच्चे को गोली मार दी गयी और इस मुत्तलिक कोई शिकायत न हो, उसके मां-बाप का कत्ल कर दिया गया । इससे बड़ा जुल्म और कोई हो सकता है ? अखबारों में यह रिपोर्ट आयी है । मैं यह जानना चाहूंगा कि जिन लोगों ने यह कार्य किया है उनको क्या सजा दी गयी है ? अगर उनको कोई सजा नहीं दी गयी तो फिर उनके हौसले बुलंद हो जायेंगे और आप कभी भी कश्मीर को संभाल नहीं पायेंगे । यहां अभी शर्मा जी जब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने बाबरी मस्जिद का जिक्र छेड़ दिया । क्या इसके साथ भी कश्मीर का ताल्लुक है ? तो कश्मीर में जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक ताकत है जो कश्मीर को हिन्दुस्तान से अलग रखना चाहती है और एक ताकत है जो कश्मीर को हिन्दुस्तान में रखना चाहती है । इस मस्जिद के टूटने की वजह से किस का हाथ मजबूत हुआ ? जो लोग कश्मीर को अलग करना चाहते हैं या जो लोग कश्मीर को हिन्दुस्तान में रखना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत हुए ? यह गौर करने की बात है । इस सवाल का जवाब तलाश करना चाहिये । इसलिये कि सारे मसायल का ताल्लुक एक दूसरे से होता है । कश्मीर में अगर मन्दिरों पर हमले हुए तो यकीनन वह काबिले मज़म्मत है लेकिन उसके जवाब में कहीं मस्जिद पर हमला होने की हिमायत नहीं की जा सकती है । हम लोग तो सेकुलर हैं और हमारे लिए सारे मज़हब एक-सा है । सबका हम बराबर एहतराम करते हैं, न किसी का ज्यादा और न किसी का कम । लेकिन इन्साफ तो एक ही होगा न या एक जगह इन्साफ एक किस्म का होगा और दूसरी जगह दूसरी किस्म का होगा ? अभी मस्जिद टूट गई । तमाम अच्छे और समझदार लोगों को सदमा पहुंचा । हिन्दुस्तानभर के लोगों को भी पहुंचा, कश्मीर के लोगों को भी पहुंचा, कश्मीर के मुसलमानों को भी पहुंचा । कश्मीर के मुसलमानों के दिल में यह खौफ पैदा हो गया कि हिंदुस्तान में

जब मस्जिद टूट रही है, हम अगर हिन्दुस्तान में रहने का जो फैसला कर चुके हैं अगर इस पर बरकरार रहे तो हमारी मस्जिदें कितने दिनों तक सलामत रहेंगी। इस सवाल का कोई जवाब है? अगर कोई जवाब है तो आप बता दें, जो जवाब है हम वही कश्मीर के लोगों को समझायेंगे। इसलिए हमको तमाम बातों के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। (समय की घंटी)। मेरा आखिरी प्वाइंट जो है वह यह है कि कश्मीर के मसले को उलझाने में कांग्रेस गवर्नमेंट और कांग्रेस पार्टी का हाथ सबसे ज्यादा है। वैसे तो सन 1947 से ही यह मामला उलझा हुआ है लेकिन जब से डा० फारूख अब्दुल्ला की हुकूमत तोड़ी गई तो हालात ने बिलकुल एक नया मोड़ अख्तियार कर लिया और हालात काबू के बाहर हो गये। उसके बाद तीन साल से ज्यादा सदर राज चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के अन्दर एक खराबी यह है कि किसी रियासत में अगर कोई गैर-कांग्रेसी हुकूमत बन जाती है तो वह उसको बर्दाश्त करना नहीं चाहती है। इससे मुल्क में जम्हूरियत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कश्मीर में यही हुआ है। एक गलत फैसला हुआ उससे कितने दिनों तक सज़ा मिलेगी, कोई नहीं जानता।

तारीख की आंखों ने वो वक्त भी देखा है,
लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई।

इसलिए अभी कश्मीर की हालत क्या है?

लोग घरों से निकलते डरते हैं,
रास्ते सांय-सांय करते हैं,
मौत हर मोड़ से गुज़रती है,
हर तरफ फौज गश्त करती है।
गोलियां सनसनाती हैं सर पर,
मौत करती है रक्स सड़कों पर।

यह है आज का कश्मीर। अगर इसको आप बचाना चाहते हैं तो तमाम सेकुलर ताकतों को मुत्ताहिद करके और कश्मीरी अवाम का एतमाद हासिल करने की कोशिश करें। सरकारी सतह पर जो कार्यवाही मुनासिब हो वह की जाए और अवाम के दिलों में उतरने का इंतज़ाम किया जाए। यही बात कह कर आप जो मुतालबा लाए हैं, हम इसकी हिमायत करते हैं, और 6 महीने के लिए सदर राज की तौसी से इत्तेफाक का इज़हार करते हैं। शुक्रिया!

شری محمد امین (پشچمی بنگال): محترم وائس چیرمین صاحب۔ چھ مہینے کے بعد مرکزی حکومت پھر اپنے چہرے پر ناکامیوں کی راکھ مل کر توسیع مانگنے کے لیے چلی آئی ہے۔ چھ مہینے پہلے جو کچھ کہا گیا تھا۔ اور اس سے جو امید بندھی تھی۔ اس پر پھر ایک بار پانی پھر گیا۔ کشمیر کا مسئلہ اور الجھ گیا ہے۔ چھ مہینے پہلے جب اس ایوان میں بحث ہوئی تھی تو کئی ممبروں نے یہ صلاح دی تھی کہ کشمیری عوام کے دل میں اترنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مسئلہ سیکیورٹی فورسز کے ذریعے حل ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اس بیچ میں کوئی مثبت قدم نہیں اٹھایا گیا۔ کشمیر میں دو طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ ایک تو وہ جو کشمیر کو ہندوستان سے الگ کرنا چاہتی ہے اور دوسری وہ طاقت ہے جو کشمیر کو ہندوستان میں رکھنا چاہتی ہے۔ اور کشمیری عوام کے جو حقوقی مسائل ہیں۔ ان کو حل کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے حکومت کو ایسے قدم اٹھانے چاہیے۔ کہ جو طاقت کشمیر کو ہندوستان سے الگ کرنا چاہتی ہے۔ وہ طاقت الگ تھلگ ہو جائے۔ جو لوگ کشمیر کو ہندوستان میں رکھنا چاہتے ہیں ان کے قدم مضبوط ہوں۔ ان کا اعتماد حاصل ہو۔ تو ہوا کیا۔ اب جماعت اسلامی کھلم کھلا کشمیر کا پاکستان سے الحاق چاہتی ہے ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں رویہ ایک قسم کا ہوگا۔ ایک اور تنظیم ہے جس کا نام "جموں کشمیر محاذ آزادی" ہے یعنی جے۔ کے۔ ایل۔ ایف۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے عوام کو اختیارات ملیں۔ ان کے مسائل حل ہوں۔ یہ بالکل حقوقی بات ہے۔ اس لیے ہماری حکومت نے کیا کوئی ایسی کوشش کی ہے کہ جموں کشمیر

پیچھے امریکی سامراجیہ واد کی پشت پناہی ہے ہماری حکومت امریکہ کے پاس بار بار دوڑ کر جارہی ہے۔ کہ کشمیر کے معاملہ میں پاکستان کو ٹیرورسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے۔ اور امریکہ کیا کر رہا ہے۔ امریکہ اس کو حقوق انسانی کا سوال بنا رہا ہے۔ جس کی ہمیں پھر مدافعت کرنا پڑتی ہے۔ مرکزی حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ کشمیر کے بارے میں امریکہ ہندوستان کی مدد کرے گا۔ تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اگر یہ غلط فہمی کسی قدر دور ہو جائے تو اتنا ہی اچھا ہے۔ امریکہ سامراجیہ واد صرف اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں دشمنی بڑھتی جائے۔ اور اس کے لیے کشمیر ایک موضوع بنا رہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنا کام بنانا چاہتا ہے۔ اس بات کو حکومت اگر سمجھتی بھی ہے تو صاف لفظوں میں کہتی نہیں ہے۔ کیونکہ حکومت کو ہمیشہ اس بات کا ڈر ہے اگر وہ امریکہ پر تنقید کرے گا تو عالمی بینک اور مانیٹری فنڈ سے پیسہ نہیں ملے گا۔ یہ ان کی کوشش ہے اور اس طرح سے یہ معاملہ بگڑ رہا ہے۔ الجھ رہا ہے۔ کشمیر کی عوام دو طرح کے ظلم کی شکار ہے۔ ایک طرف تو دہشت پسند ان کو قتل کر رہے ہیں اور دوسری طرف سیکیورٹی فورسز جوابی کارروائی کر رہی ہیں۔ اس کا شکار بھی وہی لوگ ہوتے ہیں اگر وہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ کوئی حادثہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت سیکیورٹی فورسز کا کہیں محاذ آزادی کے ساتھ رابطہ قائم کیا جائے۔ ان کو بات چیت میں لیا جائے۔ ایسی کوئی کوشش دیکھنے میں نہیں آئی۔ حکومت ۲۳ ارب ۴۱ کروڑ ۲۳ لاکھ ۸ ہزار روپے مانگ رہی ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے اس کے سوائے کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ پیسے دینے کی رائے دیں اور صدر راج کی توسیع کا بھی اعلان کریں کیونکہ یہ بات صحیح ہے کہ الیکشن کرانے کی حالت ابھی بھی نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے جو بس پسنجروں کا قتل کیا گیا اس سے بہت مورتحال واضح ہوتی ہے۔

میں جو لوگ قتل کیے گئے ہیں۔ ان کے ورثا سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ان کی مذمت کرتا ہوں۔ ایک فرقہ کے لوگوں کو مارا گیا اور اس طرح سے دہشت گردی کا جواب دہشت گردی سے دینے کی کوشش کی گئی۔ جو مارے گئے وہ معصوم تھے۔ وہ بے گناہ تھے۔ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ظلم بہر حال ظلم ہے۔ چاہے کسی فرقے کے اوپر ہو اور ملک کے کسی حصے میں ہو۔ اس کی بلا امتیاز مذمت ہونی چاہیے۔ جناب میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ کشمیر کی حالت کو بگاڑنے میں پاکستان کا ہاتھ ہے۔ اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن پاکستان یہ خود اپنی طاقت پر نہیں کر رہا ہے۔ اس کے

نیچے کی سطح پر بھی تاکہ گاؤں کے لوگ اس کے پاس پہنچ سکیں اور وہ اپنی تکلیفوں کو بغیر کسی خوف کے بیان کر سکیں اور پھر ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے قدم اٹھائے جائیں۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر میرے حساب سے بندوق کے زور سے کشمیر میں امن بحال نہیں کرایا جاسکتا ہے۔ حالات معمول پر نہیں لائے جاسکتے ہیں۔ ابھی مولانا نے ایک واقعہ بیان کیا کہ اسکول پڑھنے والے دس سال کے بچے کو گولی مار دی گئی اور اس متعلق کوئی شکایت نہ ہو اس کے ماں باپ کا قتل کر دیا گیا۔ اس سے بڑا ظلم اور کوئی ہو سکتا ہے۔ اخباروں میں یہ رپورٹ آئی ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے یہ کارنامے کیا ہے۔ ان کو کیا سزا دی گئی ہے۔ اگر ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی تو پھر ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ اور آپ کبھی بھی کشمیر کو سنبھال نہیں پائیں گے۔

یہاں ابھی شرما جی جب تقریر کر رہے تھے۔ تو انھوں نے بابری مسجد کا ذکر چھیڑ دیا۔ کیا اس کے ساتھ بھی کشمیر کا تعلق ہے۔ تو کشمیر میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک طاقت ہے جو کشمیر کو ہندوستان سے الگ رکھنا چاہتی ہے اور ایک طاقت ہے جو کشمیر کو ہندوستان میں رکھنا چاہتی ہے۔ اس مسجد کے ٹوٹنے کی وجہ سے کس کا ہاتھ مضبوط ہوا۔ جو لوگ کشمیر کو الگ کرنا چاہتے پتہ نہیں چلتا۔ لوگ مر جاتے ہیں۔ گھروں کو آگ لگا کر جلا دیا جاتا ہے۔ انکو لوٹ لیا جاتا ہے۔ قتل ہو جاتے ہیں۔ آگ زنی ہو جاتی ہے۔ تب سیکیورٹی فورسز کے لوگ پہنچتے ہیں اور جب وہ پہنچتے ہیں تو پھر وہ جب اپنی کارروائی کرتے ہیں تو اس کے شکار بھی یہی معصوم لوگ ہوتے ہیں۔ جو قصوروار ہیں وہ کبھی کبھار ہی گرفت میں آتے ہیں۔ زیادہ تر نہیں آتے ہیں۔ اس لیے کشمیر کی عوام کے دل میں یہ جو فورس بارڈر سیکیورٹی فورس اور سی۔ آر۔ پی ایف۔ جو یہ پیرا ملٹری کے لوگ ہیں۔ یہ سارے لوگ خراب نہیں ہیں۔ یہ بات کوئی نہیں کہے گا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں۔ جو غلط کام کرتے ہیں۔ چاہے جان بوجھ کر کر رہے ہوں یا انجانے میں کر رہے ہوں۔ لیکن عام لوگوں کی نگاہ میں جتنے بھی وردی پوش ہیں وہ سب ظالم ہو گئے ہیں۔ جب کسی معاملے میں حکومت کا امپریشن بگڑ جاتا ہے تو پھر اس کو ٹھیک کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ اس لیے حکومت کو جو قدم اٹھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کی شکایتیں ہیں تو یہ سوچے کہ وہ ان شکایتوں کو لیکر کہاں جائیں۔ اس طرف کے ایک ممبر نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وہاں فریاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے بہت پہلے کہا تھا کہ ایک مشاورتی کمیٹی بنائی جائے۔ پورے جموں اور کشمیر کی سطح پر اور

... میرا آخری پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو الجھاتے میں کانگریس گورنمنٹ اور کانگریس پارٹی کا ہاتھ سب سے زیادہ ہے۔ ویسے تو ۱۹۴۷ء سے ہی یہ معاملہ الجھا ہوا ہے۔ لیکن جب سے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی حکومت توڑی گئی تو حالات نے بالکل ایک نیا موڑ اختیار کر لیا۔ اور حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ اس کے بعد تین سال سے زیادہ صدر راج چل رہا ہے۔ کانگریس پارٹی کے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ کسی ریاست میں اگر کوئی غیر کانگریسی حکومت بن جاتی ہے تو وہ اس کو برداشت کرنا نہیں چاہتی ہے۔ اس سے ملک میں جمہوریت کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ کشمیر میں یہی ہوا ہے۔ ایک غلط فیصلہ ہوا اس سے کتنے دنوں تک سزا ملے گی۔ کوئی نہیں جانتا۔

تاریخ کی آنکھوں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے۔
قوموں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی

اس لیے ابھی کشمیر کی حالت کیا ہے۔

لوگ گھروں سے نکلتے ہیں
راستے سائیں سائیں کرتے ہیں
جیپ ہر موڑ سے گزرتی ہے
ہر طرف فوج گشت کرتی ہے
گولیاں سنسناتی ہیں سر پر
موت کرتی ہے رقص سڑکوں پر

ہیں یا جو لوگ کشمیر کو ہندوستان میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے ہاتھ مضبوط ہوئے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ سارے مسائل کا تعلق ایک دوسرے سے ہوتا ہے۔ کشمیر میں اگر مندروں پر حملے ہوئے تو یقیناً یہ قابلِ مذمت ہے لیکن اس کے جواب میں کہیں مسجد پر حملہ ہونے کی حمایت نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہم لوگ تو سیکولر ہیں اور ہمارے لیے سارے مذہب یکساں ہیں۔ سب کا ہم برابر احترام کرتے ہیں۔ نہ کسی کا زیادہ نہ کسی کا کم۔ لیکن انصاف تو ایک ہی ہوگا نہ۔ یا ایک جگہ انصاف ایک قسم کا ہوگا اور دوسری جگہ دوسری قسم کا ہوگا۔ ابھی مسجد ٹوٹ گئی۔ تمام اچھے اور سمجھدار لوگوں کو صدمہ پہنچا۔ ہندوستان بھر کے لوگوں کو بھی پہنچا۔ کشمیر کے لوگوں کو بھی پہنچا۔ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی پہنچا۔ کشمیر کے مسلمانوں کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ ہندوستان میں جب مسجد ٹوٹ رہی ہے۔ ہم ہندوستان میں رہنے کا جو فیصلہ کر چکے ہیں۔ اگر اس پر برقرار رہیں تو ہماری مسجدیں کتنے دنوں تک سلامت رہیں گی۔ اس سوال کا کوئی جواب ہے۔ اگر کوئی جواب ہے تو آپ بتا دیں جو جواب ہے وہی کشمیر کے لوگوں کو سمجھائیں گے۔ اس لیے ہم کو تمام باتوں کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ... وقت کی گھنٹی

یہ ہے آج کا کشمیر۔ اگر اس کو آپ بچانا چاہتے ہیں تو تمام سیکولر طاقتوں کو متحد کر کے اور کشمیری عوام کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سرکاری سطح پر جو کارروائی مناسب ہو وہ کی جائے اور عوام کے دلوں میں اترنے کا انتظام کیا جائے۔ یہی بات کہہ کر آپ جو مطالبہ لائے ہیں۔ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اور چھ مہینے کے لیے صدر راج کی توسیع سے اتفاق کا اظہار کرتے ہیں۔

شکریہ

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर के संबंध में हर 6 महीने में राष्ट्रपति शासन बढ़ाए जाने के संबंध में गृह मंत्री की ओर से संकल्प या प्रस्ताव और विनियोग विधेयक संसद में आता है। विनियोग विधेयक को चर्चा करने बाद हम लोग वापिस कर देते हैं और राष्ट्रपति शासन बढ़ाए जाने के संकल्प को पारित करते हैं। यह एक रस्म-अदायगी-सी हो गई है। लेकिन यह सही है कि जो जम्मू-कश्मीर के नागरिक हैं वह अपने को आज राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं पाते हैं। जम्मू-कश्मीर में कोई भी लोकतान्त्रिक ढांचा आज वहां पर नहीं है, न वहां पर पंचायतें हैं, न वहां पर विधान सभा है और अब वहां पर विधान सभा नहीं है तो विधान सभा के प्रतिनिधि इस राज्य सभा में भी नहीं हैं सिवाय एक को छोड़ करके जम्मू-कश्मीर से लोक सभा के सदस्य नहीं हैं। यही नहीं 1991 में सारे देश में जनगणना हुई लेकिन जम्मू-कश्मीर में जनगणना नहीं हुई। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने जिक्र किया कि वहां जो राज्यपाल की व्यवस्था है—गृह मंत्री जी ने भी घोषणा की थी पिछली बार कि आम लोगों का वहां पर प्रशासन में सम्पर्क हो, साझेदारी हो, इसके लिए एक वहां पर सलाहकार परिषद या एक कमेटी वहां पर बनायी गयी है। लेकिन उस कमेटी की कितनी बैठकें होती हैं या पिछले समय में उसकी कितनी बैठकें हुई हैं इसके सिलसिले में जब आपना उत्तर देंगे तो बताने की कृपा करें।

मैं तो यह समझता हूं कि आज बहुत जरूरी है कि जो जम्मू-कश्मीर के लोग हैं उनको इस बात का आहसास होना चाहिए कि वे भारतवर्ष के नागरिक हैं। हम लोग नारा लगाते हैं कि जम्मू-कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और दुनिया की कोई ताकत जम्मू-कश्मीर को आज हमसे अलग नहीं कर सकती, विच्छेद नहीं कर सकती। दूसरा नारा हम लगाते हैं कि जम्मू-कश्मीर की समस्या का समाधान या जो कुछ भी इस सिलसिले में कहना चाहिए कि मतभेद है उसका समाधान केवल शिमला समझौते के अंतर्गत होना चाहिए। लेकिन सही मायनों में मैं आज पूछना चाहता हूं कि क्या यह जो बेली का स्थान है—कश्मीर के में समझता हूं कि चार हिस्से हैं, एक लद्दाख, दूसरा जम्मू का हिस्सा, तीसरा घाटी का और चौथा वह हिस्सा जिसको आजाद कश्मीर कहा जाता है—वह भी जबर्दस्ती ही दूसरे देश ने कब्जा करके रखा हुआ है। लेकिन आज सही मायनों में जो घाटी का हिस्सा है वहां पर भारत सरकार की कोई रिट, भारत सरकार का कोई आदेश चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है? क्योंकि आये दिन वहां पर घटनाएं होती रहती हैं। आतंकवादी वहां पर हावी हैं, उग्रवादी वहां पर हावी हैं और ऐसे आतंकवादी और उग्रवादी हैं जिनको हमारा जो पड़ौसी देश है—जो लोग कभी इस देश के अंग थे वही लोग उनको सहायता दे रहे हैं, उभार रहे हैं भारत के खिलाफ। लेकिन इसके बाद भी मैं यही कहूंगा कि भारतवर्ष की ओर से उस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती है, उसके प्रचार की दृष्टि से जिस प्रकार से पाकिस्तान कर रहा है।

एक कोई मैलट साहब हैं, भारतवर्ष आये थे। उनकी हैसियत वही है जो भारतवर्ष के किसी एक मामूली से सचिवालय में बैठे हुए ज्वाइंट सेक्रेटरी की, संयुक्त सचिव की होती है। लेकिन मैलट साहब जब यहां आये और जो उन्होंने उद्गार व्यक्त किये उन पर तो मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जिस तरीके से मैलट साहब का प्रचार किया गया, सरकारी मीडिया ने जिस तरीके से प्रचार किया, जिस तरीके से यहां के मंत्रियों से मिले और उसका जिस तरीके से यहां प्रचार किया गया, मैं समझता हूं यह भारत ऐसे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है और उसको बोदराया नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैलट ने जो अपने वक्तव्य दिये हैं, उन वक्तव्यों से इस देश को नुकसान हुआ है विश्व के स्तर पर। जो उग्रवादियों की गतिविधियां हैं उनको लाभ पहुंचा है मैलट के वक्तव्यों से। जो अमेरिका मुल्क है उसने इस मामले में हमारे साथ मित्रता का व्यवहार नहीं किया है।

दूसरा, कश्मीरी पंडितों की समस्या है। कश्मीरी पंडितों का वहां से पलायन हुआ। जम्मू में भी टेंटों में रह रहे हैं और दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर रह रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडित कभी जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र में वापस जायेंगे या नहीं जायेंगे यह एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह आज लग गया है। इस सिलसिले में एक बहुत ही विद्वान लेखक हैं श्री अमरीक सिंह, अभी 14 जुलाई, 1993 को कश्मीरी पंडितों पर "हिंदुस्तान टाइम्स" में उनका एक बहुत अच्छा लेख था, मैं केवल उनकी चार-पांच पंक्तियों का उद्धरण करना चाहता हूं।

> "A visit to one of the camps of Kashmiri
> Pundits at the end of May, 1993, where the migrants are lodged in Jammu was

difficult to believe that any Government, even an incompetent Government, could be a party to such sin arrangement."

उनका वहां पर एक संघ भी है । वे लोग एक पत्रिका भी निकालते हैं, जिसका नाम है "ओशो समाचार" । शायद माहवारी पत्रिका है । कितनी इन लोगों की दुर्दशा है, इनको बेचारों को जबरदस्ती वहां से पलायन करना पड़ा और आज भी जब वे कैम्प में रह रहे हैं, तो एक मनुष्य की तरह उनको जीवन नहीं जीना पड़ रहा है, बल्कि एक जानवर से बदतर जिंदगी उनकी वहां पर हो रही है ।

इसलिए भारत सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए ।

अभी श्री ओबैदुल्ला आज़मी जी राष्ट्रीयता पर चर्चा कर रहे थे और बहुत ही राष्ट्रीयता से ओतप्रोत उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये और उन्होंने भी ध्यान आकर्षित किया है कि जो भारत के लोग हैं, वे भारत में ही रहना चाहते हैं और कश्मीर चूंकि भारत का एक अविभाज्य अंग है, तो भारत सरकार को इस सिलसिले में सख्ती से कदम उठाना चाहिए ।

दूसरे, वहां पर एक वैष्णो देवी ट्रस्ट है । मैं जानना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, जब उत्तर दें कि वैष्णो देवी ट्रस्ट में कौन-कौन लोग सदस्य हैं क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है—मैं कह नहीं सकता कि वह ठीक है या गलत है—कि वैष्णो देवी का ट्रस्ट जो है, उसके जो ट्रस्टीज़ हैं, उनकी नियुक्ति सरकार की ओर से होती है ।

मैं जानना चाहूंगा कि वैष्णो देवी ट्रस्ट जो है, उसके कौन-कौन सदस्य हैं और उसकी कोई बैठक भी कभी होती है कि नहीं होती है क्योंकि मुझे बताया गया है कि वैष्णो देवी ट्रस्ट की पिछले छह महीने में एक भी बैठक नहीं हुई है ।

अब 6 जनवरी को सोपोर में एक कांड हुआ । दो सौ दुकानें वहां पर जल गईं तथा आधी दर्जन से अधिक, सात गोदाम वहां पर जल गये और आगज़नी में पचास लोगों की मृत्यु हो गई । उसके संबंध में शायद कोई न्यायिक आयोग बिठाया गया था ।

तो मैं यह भी जानना चाहूंगा कि उस न्यायिक आयोग ने अपनी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि नहीं ? और अगर नहीं की है, तो उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करने में क्यों देरी है, विलम्ब क्यों है ? उस सिलसिले में भी गृह मंत्री जी अवगत कराने की कृपा करें । वहां के जो वर्तमान राज्यपाल हैं, उनके बारे में यह कहा जाता है कि उनका जनता से कोई सम्पर्क नहीं है । चाहे राज्यपाल हों या राज्यपाल के सलाहकार हों, उनका वहां की जनता से कोई भी सम्पर्क नहीं है । तो जब राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल और राज्यपाल के सलाहकार का वहां की गरीब जनता से सम्पर्क नहीं होगा, तो आखिर जनता अपने कष्टों को, अपने दुख-दर्द को बताने के लिए किसके पास जाएगी ।

अभी हाल में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भी वहां पर गया था । उसमें इस सदन के सदस्य श्री महेन्द्र सिंह लाठर और श्री जगदीश प्रसाद माथुर भी थे । जिस प्रकार का व्यवहार जन-प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल महोदय ने किया, वह एक जनतान्त्रिक मुल्क के लिए बहुत ही कलंक की बात है । वह एक मिलिट्री के अफसर रहे होंगे, मिलिट्री के कमांडर रहे होंगे, जनरल रहे होंगे, लेकिन जम्मू और कश्मीर में जहां पर कि बहुत आवश्यकता है कि आम जनता से, लोगों के सम्पर्क में रहें और आम लोगों की कठिनाइयों को समझें और समझ करके उनका समाधान करने की कोशिश करें । तो मैं तो यही समझता हूं कि वर्तमान राज्यपाल के चलते, जहां तक कि जनता की कठिनाइयों का संबंध है, उसके समाधान में बहुत कठिनाई है ।

इस पर भी भारत सरकार को विचार करना चाहिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ विनियोग विधेयक पर और जो गृह मंत्री जी का संकल्प या प्रस्ताव है, उस पर मैं अपने विचार रखता हूं ।

THE VICE CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Shri S. Muthu Mani. Not present. Shri Prakash Yashwant Ambedkar. Not present. Shri Bhupinder Singh Mann. Not Present. Prof. Saurin Bhattacharya*Interruptions)* ...
Members belonging to other Groups are left behind. They should also be given a chance to speak early.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal) : Mr.Vice-Chairman. Sir. the issue that is before us is a very old issue. Under the Presidents rule itself, there is a problem of terrorism, etc. organised from across the border, for which the people of Kashmir have to pay a very heavy price. Many times, they had to give up their self-governmeni. They had been under President's rule for quite some time and very often persons responsible for conducting Kashmir under President's rule proved themselves unequal to the task either by bungling or by committing some other faults. As it is. the present rule is under a former Chief of Stall of the Indian Army, Gen. K. V. Krishna Rao. Mere designation may not carry a person very far in this task—a very delicate task and a very responsible task for any one.

So far as the Government of India is concerned, they have always been providing a wrong signal to the people of the country through both the Houses of Parliament regarding the position obtaining in Jammu and Kashmir. A false sense of security is sought to be created one day and the other day a completely different picture is made available. *We* were told that Kashmir was almost ready for a

political process to start. As a matter of fact, perhaps. President's rule is sought to be renewed for the fourth time through a constitutional amendment in Kashmir. It was done in respect of Punjab and Kashmir. In Punjab, a sort of representative Government has been established. But in the case of Kashmir. it seems to be *hunooz door ast.* And the Governor of Kashmir has been talking in so many tongues, in so many conflicting ways that the people can at the best be confused by what he has been saying. It has been remarked earlier that perhaps when the Governor is a person who has no connection with the people of the State, who is not of the State by his training, by his duties earlier, hecannot be expected to be very good in having contact with the common people. Now. in addition to that, he has taken up cudgels against the political people also : that in no way they would be allowed to have a say in the affairs of Kashmir. Either the people or the politicians ■■ who are supposed to be there, who are the representatives of the people, would not have anything to do with what is happening in Kashmir. It is only the former Army Chief who will have the final say. That is the situation. Perhaps there is no remedy; perhaps clearance for further extension of the President's Rule in Kashmir is necessary. But that won't lead to any improvement in the position of Kashmir. It is no use wailing over the role of Pakistan or some other forces behind Pakistan, unless we are able to improve the internal conditions in Kashmir in all respects, so far as the economic activities are concerned, so far as employment is concerned and so far as gradual paving the way for restoring the political process there is concerned If all these cannot be done and if continuous extension of President's Rule is made, may be through another Constitutional amendment which may perhaps be permissible, things will not improve and this will not lead us anywhere. I only hope that the Government will do good both for Kashmir and for the entire country. Thank you. Sir.

SHRI N. GIRI PRASAD (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is inevitable under the present situation to pass the Appropriation Bill for Kashmir and it is also inevitable that we have to extend the President's Rule under article 356 of the Constitution for a further period of six months because the situation in Kashmir has not improved and opportunities have not been created or a favourable situation has not been created there to hold elections. Hence I consider this as inevitable. But I hope that by the efforts of the Government by the efforts of all the political parties, the situation there would improve and the people of Kashmir have to be convinced that their cause will be much better served through the democratic process, , through their participation in democratic elections.

In this connection. I want to make some comments. This is a problem created, to some extent, by external forces and. to a greater extent, it is our own creation. I am saying this because, in the past, many elections except in one. all of them were rigged in order to capture power through undemocratic means. That has created a particular impression among a large number of people in Kashmir that their verdict, that their participation in democratic elections, will not bearany result and the ruling party will have its own say through these rigged elections. Moreover, when Dr. Farooq, Abdullah was removed, and when he was given power after some consultations, he was forced to share power with the Congress (I). In fact, that was a political mistake. If the Congress CI) was acting as a democratic Opposition or secular Opposition to Dr. Farooq Abdullah and his National Conference, there would have been two political parties coutending against each other and a democratic and secular set-up would have been there and that would have saved a lot of trouble in Kashmir.

The other aspect is the international dimension of the Kashmir problem. Of course, from the very beginning, Pakistan was never happy that Kashmir was made an integral part of India. But they could not do much till almost four years back. During these four years, not only the people of Kashmir were alienated, but also the involvement of Pakistan has been proved. Now, there is infiltration from Pakistan into Kashmir and there is movement from Kashmir to Pakistan, and they are training a large number of people. All this information we know. But, recently, the most alarming reports have come in. Some mercenaries from Afghanistan and may be some other countries are being sent here. As late as last Tuesday, the 'New York Times' published that about 400 mercenaries are working in India against the Indian Armed Forces. And there was another report that there was a pitched battle between the mercenaries and our Armed Forces in the Vasudhara hills of Doda district, where almost ten BSF jawans were killed and a good number of jawans were also captured. I do not know whether this report was confirmed by the Government. But such reports have also appealed.

What I want to say is that Pakistan's involvement is growing more and more. And Pakistan is emboldened also. This they tried in Punjab. Fortunately, in Punjab, because of political enlightenment and also Government's measures to curb such illegal entry of those forces, that stopped and the people are now heaving a sigh of relief As far as Kashmir is concerned, they are creating another problem. The problem is of communal division. And you know that is one State where the Muslims are in a majority. And naturally. Pakistan, based upon some Islamic fundamentalism, wants to provoke the people or divide the people of Kashmir on communal lines. This is not the first time. I remember, during 1947 and 1950 also, there was one Anglo-US Commission. And there was one UN representative also, Even then they were trying to carve out a Greater Kashmir where the Muslims are in a majority. That is how this Doda problem also was created at that time. A new Doda district was created from Udhampur or something. And the Kargil District in Ladakh was also created where they wanted to * see that the Muslims are in a majority. This was a scheme of the Anglo-US leaders at that time to divide Kashmir on communal lines. This was the demographic solution that they wanted to have at that time. Fortunately, that diabolical scheme or sinister aim of the US-British imperialists could not succeed. But. even now, I feel that there is some amount of illusion in our Government about the US Administration. I do not know what our Foreign Secretary will bring from America after his talks with the US Administration there. But. as far as the reports are concerned, in spite of the Congressional Task Force giving report about Pakistan's involvement in these affairs, the US State Department is not in a position to agree with it. Moreover, they have given a clean certificate to Pakistan. Their representative, one Mr. McCurry said:

> "We reached this determination because Pakistan has taken a number of important steps that appear to have responded to our concerns about reports of official support for Kashmiri and other militants who committed terrorist acts. Islamabad has been training Sikh and other Indian separatist movements as part of Bhutto's strategy for forward strategy depths and also as part of his effort to take revenge for India's support of an independent Bangladesh."

So, they want to take revenge, and the US are giving a clean certificate to Pakistan that Pakistan is not a terrorist State and that they are not involved very much. I think, the Government must take up this issue also in a big way.

Lastly, 1 want to say that the main battle now before the Government and the people is to win over the hearts of the Kashmiri people. This cannot be done by committing excesses. There were two or three excesses. But these are being highlighted very much in the international fora as human rights violations and abuses. All these things-must not give a handle to other forces to beat us on this score. And where there is no crossfiring if unnecessarily innocent people are killed, that gives wrong signals. That will alienate people more from coming back to the mainstream. That is why, the Government should take every step to win over the People.

In the Annual plan they have provided only Rs. 80 crores. I do not know how the Government will be able to develop Kashmir or help the people there or provide employment to the People of Kashmir with this meagre amount. The Government must provide more and more hinds and create more and more opportunities for employment so that Ihe Kashmiri people can be drawn towards the mainstream of Indian politics.

श्री मोहम्मद ख़लीलुर रहमान (आन्ध्र प्रदेश) : जनाब वाइस चेअरमैन साहब, कश्मीर का मसला इन्तहाई हस्सास मसला है और यह लॉ एंड आर्डर का मसला कभी भी नहीं रहा । लिहाज़ा इस मसले को इंतहाई एहतियात के साथ हल करने की ज़रूरत है । 1947 में जबकि कश्मीरी आवाम ने अपने आपको हिन्दुस्तान से मुलहक़ किया तो उनकी उम्मीदें, उनकी तमन्नाएं, उनकी आरज़ूएं ये थीं कि हम हिन्दुस्तान के साथ रहेंगे, हिन्दुस्तान के साथ घुले-मिलेंगे और हिन्दुस्तान के साथ हम अपने मुस्तकबिल को वाबस्ता करेंगे । मगर जिस तरह से कश्मीरियों के साथ इन पिछले 40—45 बरसों में बर्ताव होता रहा, उससे कश्मीरी आवाम के मन में एक बेचैनी पैदा होती रही है । इसमें शक नहीं कि करोड़ों-अरबों रुपए हमारी मरकज़ी हुकूमत से कश्मीर में जाते रहे, मगर सही मायने में वह वहां के आवाम के फलाह-व-बहबूद पर और आवाम की तरक्की पर खर्च नहीं किए गए । इससे एक किस्म की बेचैनी उन लोगों में पैदा हुई ।

दूसरी बात यह है कि मुख्तलिफ इलेक्शन वहां पर करवाए गए । सही मायनों में कोई इलेक्शन भी ऐसा नहीं रहा कि वहां के आवाम का मज़हर रहा हो और उनकी उम्मीदों व तमन्नाओं का मज़हर रहा हो । हमेशा रिगिंग के ज़रिए वहां पर हुकूमतें मुसल्लत होती रहीं । वे सब वाक़यात इस किस्म के रहे कि वहां के आवाम में एक बेचैनी पैदा होती रही और फिर खास तौर पर जो

मुखालफत वाले लोग थे, जो अलाहदगी-पसंद लोग थे, उन अलहदगी पसंद लोगों के जुज्बात और उजागर हो गए और उन्होंने वहां के आवाम का इस्तेहसाल करना शुरू किया । अब सूरतेहाल यह है कि कश्मीर की मईशत मुकम्मिल तबाह होकर रह गई है ।

आप अच्छी तरह से जानते है कि कश्मीरी आवाम का ज़राए आमदनी टूरिज्म था । टूरिज्म से न सिर्फ कश्मीरी आवाम की ज़िंदगी बसर होती थी बल्कि हिन्दुस्तान भी काफी करोड़ों का फारेन एक्सचेंज उस टूरिज़्म से कमाता था । आज वहां के जो कुछ भी हालात हैं, उससे वहां का टूरिज्म मुकम्मिल तबाह हो गया है और कश्मीरी आवाम की जो मेन ज़राए आमदनी थी वह मुतासिर हो गई है ।

उसके बाद जो हेंडीक्राफ़्ट था, वह उनका दूसरा ज़राए आमदनी था । जब टूरिज्म ही मुतासिर हुआ तो ज़ाहिर है कि वहां हेंडीक्राफ़्ट भी मुतासिर हुआ । इस लिहाज़ से भी वहां के कश्मीरी आवाम की जो ज़राए आमदनी थी, मईशत थी, वह भी मुतासिर होती चली गई ।

तीसरे, वहां का हॉर्टीकल्चर खास तौर पर सेब और ज़ाफरान की काश्त भी इन हालिया अर्सों में टेरेरिज्म और वहां की मुसलसल फ़िज़ा, जो वहां पैदा हुई है, उसमें वह भी मुतासिर हुआ है और सही मायनों में कश्मीर का सेब, जो पूरी दुनिया में मशहूर था और जाना-पहचाना जाता था, उस सेब की काश्त में कमी हुई है और ज़ाफरान तो बिल्कुल ही ठन्डा हो गया है लिहाज़ा ये चीजें ऐसी हैं कि इससे वहां की आवाम की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है और ज़ाहिर है कि मईशत जब तबाह हो जाती है तो एक किस्म की बेचैनी पैदा होती है और उस पर तुर्रा यह है कि दफा 370 जो है, वह कश्मीरी आवाम की गर्दनों पर एक तलवार की तरह लटक रही है और हमारी जो सियासी पार्टियां हैं, मिसाल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी है, वह हमेशा यह कहती आ रही है कि दफा 370 हटा दी जाए और कश्मीरी आवाम यह चाहते हैं कि दफा 370 बाकी रहे और दफा 370 न हटे । उनके ज़हनों में एक किस्म का डर और खौफ पैदा हो गया है कि अगर कहीं कल के दिन भारतीय जनता पार्टी मकरज़ में इकतदार पर आ जाए तो यह हो सकता है कि दफा 370 हट जाएगा । तो लिहाजा मैं आपके तवस्सुत से अपने बी० जे० पी० के भाइयों से यह दरख्वास्त करूंगा कि बराहे करम आप जो यह दफा 370 हटाने की जो बात कर रहे हैं, वह दफा 370 हटाने की बात मत कीजिए । ऐसे कई खदसात हैं जो तमाम खदसात एक जगह जमा हो गए हैं और वहां के आवाम में एक बेचैनी पैदा हो गई है और फिर खास तौर पर यह अलाहदगी पसंद कूवतें हैं, वही उससे पूरा-पूरा फायदा उठा रहे हैं । आप देखिए कि अभी हाल में जो वाकया हुआ है कितनी गलत बात है । यह हमारे माथे पर एक बदनुमा दाग है । एक बस के मुसाफिरान को यानी एक फिरके के मुसाफिरान को अलाहदा किया जाता है और गोलियों के जरिए उनको भून दिया जाता है । यह कितना संगीनाक वाकया है । मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूं । मैं क्या तमाम हिन्दुस्तानी इसकी भरपूर मज़म्मत करेंगे । यह जो वाकया ऐसे है कि अब हमको जरूरत इस बात की है कि हम कश्मीरी आवाम का मन जीतें । वहां पर ऐसे हालात पैदा करें कि फिर वहां पर ज़िंदगी दोबारा लौटकर आ जाए और वह लोग इतहाई सकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकें । उनका जो वोट का हक है, वहां पर ऐसे हालात पैदा करें कि वहां जम्हूरियत बहाल हो सके, उसकी मईशत दुरुस्त हो सके । उनके बच्चों की तालीम मुतासिर हो गई है, मदारिस में बच्चे नहीं जा रहे हैं । वहां के टूरिज्म वगैरह के बारे में जैसा कि मैंने अभी आपके सामने ज़िक्र किया, इन सब चीजों को आप बहाल करने की कोशिश कीजिए तो यकीनन उनकी जो ख्वाहिश है कि हम हिन्दुस्तान के साथ रहेंगे, यकीनन वह हिन्दुस्तान के साथ रहेंगे और मैं आपके तवस्सुत से जनाब होम मिनिस्टर साहब से यह अपील करूंगा कि आप ऐसे हालात पैदा कीजिए कि उनका दिल जीतने की कोशिश करें ।

जो डिमांड है, मैं उसकी भरपूर ताईद करता हूं और फिर 6 महीने का जो एक्सटेंशन हमारे ऑनरेबिल होम मिनिस्टर साहब लाए हैं, हम उसकी भी ताईद करते हैं । मगर आपसे दरख्वास्त करते हैं कि फिर दोबारा मज़ीद एक्सटेंशन के लिए नहीं आएं और इन 6 महीने के अंदर ही आप ऐसे हालात पैदा करें कि वहां पर फिर जम्हूरियत बहाल हो सके । शुक्रिया ।

†قری محمد خلیل الرحمٰن • آندھرا پردیش": جناب وائس چیرمین صاحب۔ کشمیر کا مسئلہ انتہائی حساس مسئلہ ہے اور یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کبھی بھی نہیں رہا۔ لہٰذا اس مسئلے کو انتہائی احتیاط کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ۱۹۴۷ میں جبکہ کشمیری عوام نے اپنے آپ کو ہندوستان کے ساتھ ملحق کیا تو ان کی امیدیں، انکی تمنائیں، انکی آرزوئیں یہ تھیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ رہیں گے۔ ہندوستان کے ساتھ گھلے ملیں گے۔ اور ہندوستان کے ساتھ ہم اپنے مستقبل کو وابستہ کریں گے۔ مگر جس طرح سے کشمیریوں کے ساتھ ان پچھلے چالیس پینتالیس سالوں میں برتاؤ ہوتا رہا۔ اس سے کشمیری عوام کے من میں

†t (   ] Transliteration in Arabic Script

پر تباہ ہو گیا ہے۔ اور کشمیری عوام کی جو مین ذرائع آمدنی تھی وہ متاثر ہو گئی ہے۔

اس کے بعد جو ہینڈی کرافٹ تھا۔ وہ ان کا دوسرا ذریعہ آمدنی تھا۔ جب ٹورزم ہی متاثر ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں ہینڈی کرافٹ بھی متاثر ہوا۔ اس لحاظ سے بھی وہاں کے کشمیری عوام کی جو ذرائع آمدنی تھی۔ معیشت تھی۔ وہ بھی متاثر ہوتی چلی گئی۔

تیسرے وہاں کا ہارٹی کلچر خاص طور پر سیب اور زعفران کی کاشت بند ان عالیہ عرصوں میں ٹیرورزم اور وہاں کی مسلسل فضا۔ جو وہاں پیدا ہوئی ہے۔ اس میں وہ بھی متاثر ہوا ہے اور صحیح معنوں میں کشمیر کا سیب۔ جو پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اور جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس سیب کی کاشت میں کمی ہوئی ہے۔ اور زعفران تو بالکل عنقا ہو گیا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں ایسی ہیں۔ کہ اس سے وہاں کی عوام کی معیشت بالکل تباہ ہو چکی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ معیشت جب تباہ ہو جاتی ہے تو ایک قسم کی بے چینی پیدا ہوتی ہے اور اس پر طرّہ یہ ہے کہ دفعہ ۳۷۰ جو ہے۔ وہ کشمیری عوام کی گردن پر ایک تلوار کی طرح لٹک رہی ہے۔ اور ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں۔ مثال کے طور پر بھارتیہ جنتا پارٹی ہے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتی آ رہی ہے کہ دفعہ ۳۷۰ ہٹا دی جائے اور کشمیری عوام یہ چاہتے ہیں کہ دفعہ ۳۷۰ باقی رہے۔ ایک بے چینی پیدا ہوتی رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کروڑوں اربوں روپے ہماری مرکزی حکومت سے کشمیر میں جاتے رہے۔ مگر صحیح معنوں میں وہ وہاں کے عوام کے فلاح و بہبود پر اور عوام کی ترقی پر خرچ نہیں کئے گئے۔ اس سے ایک قسم کی بے چینی ان لوگوں میں پیدا ہوئی۔

دوسری بات یہ ہے کہ مختلف الیکشن وہاں پر کروائے گئے۔ صحیح معنوں میں کوئی الیکشن بھی ایسا نہیں رہا کہ وہاں کے عوام کا مظہر رہا ہو اور ان کی امیدوں میں وہ تمناؤں کا مظہر رہا ہو۔ بیلٹ بکس کے ذریعے۔ وہاں پر حکومتیں قائم ہوتی رہیں۔ یہ واقعات اس قسم کے رہے کہ وہاں کے عوام میں ایک بے چینی پیدا ہوتی رہی اور پھر خاص طور پر جو مخالفت والے لوگ تھے۔ جو علیحدگی پسند لوگ تھے۔ ان علیحدگی پسند لوگوں کے جذبات اور اجاگر ہو گئے۔ اور انھوں نے وہاں کے عوام کا استحصال کرنا شروع کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کشمیر کی معیشت مکمل تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔

آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کشمیری عوام کا ذرائع آمدنی ٹورزم تھا۔ ٹورزم سے نہ صرف کشمیری عوام کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ بلکہ ہندوستان بھی کافی کروڑوں فارن ایکسچینج اس ٹورزم سے کماتا تھا۔ آج وہاں کے جو کچھ بھی حالات ہیں۔ اس سے وہاں کا ٹورزم مکمل طور

سکیں۔ ان کا جو ووٹ کا حق ہے۔ وہاں پر ایسے حالات پیدا کریں کہ وہاں جمہوریت بحال ہو سکے۔ اس کی معیشت درست ہو سکے۔ ان کے بچوں کی تعلیم متاثر ہو گئی ہے۔ مدراس میں بچے نہیں جا رہے ہیں۔ وہاں کے ٹورزم وغیرہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے ابھی آپکے سامنے ذکر کیا۔ ان سب چیزوں کو آپ بحال کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو یقیناً ان کی جو خواہش ہے۔ کہ ہم ہندوستان کے ساتھ رہیں گے۔ یقیناً وہ ہندوستان کے ساتھ رہیں گے۔ اور میں آپ کے توسط سے جناب ہوم منسٹر صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ ایسے حالات پیدا کیجیے کہ ان کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔

جو ڈیمانڈ ہیں۔ میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ اور پھر چھ مہینے کا جو ایکسٹینشن ہمارے ہوم منسٹر صاحب لائے ہیں۔ ہم اسکی بھی تائید کرتے ہیں۔ مگر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ پھر دوبارہ مزید ایکسٹینشن کے لیے نہیں آئیں۔ اور ان چھ مہینوں کے اندر ہی آپ ایسے حالات پیدا کریں کہ وہاں پھر جمہوریت بحال ہو سکے۔ شکریہ۔

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, in regard to the Kashmir problem, basically, it is the external aspect that has accentuated the internal contradiction. Since the last few months, the U.S.A

has introduced a new element in the Kashmir dispute. They have openly said. One Under Sec-

اور دفعہ ۳۷۰ نہ ہٹے۔ ان کے ذہنوں میں ایک قسم کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا ہے اگر کہیں کل کے دن بھارتیہ جنتا پارٹی مرکز میں اقتدار پر آجائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ دفعہ ۳۷۰ ہٹ جائے۔ تو لہٰذا میں آپ کے توسط سے اپنے بی۔ جے۔ پی۔ کے بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ براہ کرم آپ جو یہ دفعہ ۳۷۰ ہٹانے کی جو بات کر رہے ہیں۔ وہ دفعہ ۳۷۰ ہٹانے کی بات مت کیجیے۔ ایسے کئی خدشات ہیں جو تمام خدشات ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ اور وہاں کے عوام میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی ہے اور پھر خاص طور پر۔ یہ علیحدگی پسند قوتیں ہیں وہی اس سے پورا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ابھی حال میں جو واقعہ ہوا ہے کتنی غلط بات ہے۔ یہ ہمارے ماتھے پر ایک بدنما داغ ہے۔ ایک بس کے مسافرین کو یعنی ایک فرقہ کے مسافرین کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ اور گولیوں کے ذریعے ان کو بھون دیا جاتا ہے۔ یہ کتنا اندوہناک واقعہ ہے۔ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ میں کیا تمام ہندوستانی اس کی بھرپور مذمت کرینگے۔ یہ جو واقعہ ایسے ہیں۔ کہ اب ہم کو ضروریات اس بات کی ہے کہ ہم کشمیری عوام کا من جیتیں۔ وہاں پر ایسے حالات پیدا کریں کہ پھر وہاں پر زندگی دوبارہ لوٹ کر آجائے۔ اور وہ لوگ انتہائی سکون کے ساتھ زندگی کے دن گزار

retary of State from the U.S. while on a visit to India said that the opinion of the people of Kashmir should be taken into consideration. This is a direct incitement to the Kashmiri terrorist groups.

We also know that, recently, the task force of the U.S. Congress—a reference to this was made by my friend—gave all the evidence that Pakistan is helping the terrorist in Kashmir by all means. In spite of all these proofs and documents,—their research was for about twenty years—the U.S. Administration disapproved the conclusion that Pakistan be declared a terrorist State. Therefore, these external factors are more important because they are creating the problems in Kashmir. That is the reason why the Kashmir problem is being discussed and every six months the Government has to come here for seeking extension of President's rule.

There is another aspect of external influence. The Islamic Conference that met in Pakistan once again supported Pakistan's stand. That also gives a lot of strength to Kashmiri terrorists. It was rightly said by one of the speakers earlier that it is the Islamic fundamentalism which is aggravating the problem. Due to *thai* Pakistan also gets some help from some of the Islamic . countries with whom they have friendly relations. Also, the Pakistan military budget has gone up by 8.4 per cent compared to last year. Now it is 35 per cent of the total Pakistan budget. That means, Pakistan is spending more than one rupee out of three rupees on defence. Why are they spending ? They know that we are never going to attack them. Yet they want to create a situation, they want to build up an atmosphere to show that they have the military might and they can create all sorts of nuisance against India. At the same time, the expenditure on Indian military in the background of rising GDP has declined. I am for that because it is not necessary for us that we go on increasing our expenditure on defence. Pakistan has also very close relations with China. Our Prime Minister is going to visit China on the 6th of next month. It is very good. The people in Kashmirhave understood that terrorists have to be isolated, but we should understand one thing that if we are going to have close relations with China, Chairman Mao Tse-tung never accepted that Tibet would be kept out of China and he had requested all the Chinese to settle there in Tibet. The workers were given double the wages. Even some people are complaining that in Tibet there is a sizeable population of Chinese. Therefore, this territorial question has to be considered carefully. Otherwise, it might create problems in future.

Islamic fundamentalism is creating some problems in Sinkiang province of China. China also knows that if this tendency is allowed to grow, it might work against them. In that background we have to solve the Kashmir problem. Of course, I do not agree with the BJP's demand for cancellation of article 370 at this juncture. From the beginning it is like that. The position would have been different if it had not been so and if we had learnt some lesson from Chairman Mao's policy that every Indian has a right to settle in Kashmir. But now it cannot be done. *M* this juncture it will create problems.

Secondly, Sir, it is unfortunate that in every problem we bring in politics. There is always the consideration of vote-bank. BJP too has an eye on the vote-bank when they say, "Cancel article 370." They are trying to get votes from one segment and those who oppose in the name of history have another angle. But what is the objectivity that Kashmir belongs to India, and if it belongs to India it cannot have a separate placement ? But I cannot say it today because that will be encouraging terrorism. Therefote, my friendly advice to the BJP is to tone down their demand about article 370 if they have national interests at heart. If you are out to win oil majority community votes, you can go ahead. But you are a patriotic party—I consider so. Therefore, kindly consider this when you talk of article 370. At the moment the people of Kashmir have to be won over, because without winning them over we cannot finally settle the issue. I know you are against discussions and negotiations. But let us get this straight You may not openly admit it. I also feel it How can you have double-talk? You are fighting the terrorists and they are not coming for negotiations. There is pressure from here that you negotiate with them, with those who do not want to negotiate with you. They want to negotiate through bullets. What can be the answer from our side ? So, at least let us detach the Kashmir issue from vote bank politics and Party politics. Let it be viewed from 'the national angle.

Now our Prime Minister is going to China. This is the right opportunity for the Prime Minister to discuss about Kashmir. When Mr. Li Peng came here to India—it is not a question of generosity—we accepted the objective fact that Tibet is an autonomous part of China. Now

the Dalai Lama has come forward and he wants to settle it on a new basis. So they should also reciprocate that Kashmir is an integral part of India. I don't say that on this point you have discussions with them, but as we have conceded—rightly conceded and not wrongly conceded—that Tibet is an autonomous part of China, in the same way China should also try to accom modate our views. If we de-internationalize this issue, if the USA is put outside the orbit if we keep China away so that no missiles will be sent, this problem can be tackled. Of course, they have offered today—I have read it in the newspapers today and it is a very good news—that they are prepared to give us a launchingbase for our satellites. Well, that is a facility, not cryogenic technology. I was carefully hearing the speech of the Prime Minister the other day about the cryogenic technology transfer, that we will try to get technology from other countries.

China is being bullied by the USA today They have imposed sanctions against China. They bullied Russia and they have tried to bully China. The Chinese will retaliate in their own way; it is a different type of country. But in thisinternational scenario the coming closer of India and China is very vital, and the Chinese may be requested to accommodate our views so that their desire of living in peace in the entire region is also realized as far as the Kashmir territory is concerned. Thank you.

SHRI JAGMOHAN (Nominated) : Sir, in view of what the Home Minister has stated yesterday and also in view of the Governor's report,there is no other option but to extend the President's Rule. I also support the Appropriation BAL

SHRI CHIMANBHAI MEHTA : Sir, I also support the Bill. Thank you.

SHRI JAGMOHAN : From the financial position as is available, I would like to point out a few things. It is evident that a lot of Central assistance is available to Kashmir. This fact is not being highlighted sufficiently by our media or by our Government both at the national and at the international level. For instance, I will 51st give a very brief point

The total population of the State of Jammu and Kashmir is 0.8 per cent of the total population of India, whereas the Central grants that are available to the State are about 3 per cent of the total grants mat are disbursed by the Central Government. So, you can just imagine how much extra assistance is being given to the State. I am for giving more assistance also. But the point is that what is being given should also be explained to the people so that they do not get the wrong impression that is being spread. I have figures for 1989-90, which I calculated while doing some academic work. I just want to share these with the House. The per capita assistance available for that period for the State was Rs. 1,124. The corresponding figures for West Bengal was Rs. 67. Just imagine it. For Bihar it was Rs. 119. For UP. it was Rs. 130. You can just imagine the extent to which it is being given, I think it is a failure of our publicity that we have not been able to project this point sufficiently.

Another relevant point is that a lot of money is being made available to it. What has been given as loan previously, has now been conver- ted into 90 per cent grant which is not to be returned. It is just a grant, and only 10 per cent is loan. How is this money being utilised ? That is the issue. I will just give you one recent example. The Deputy Commissioner of Anantnag, Mr. Vanik, has been accused of misappropriating Rs. 8.5 crores. It is wrong. The Deputy Com- missioner might have taken some money or his staff might have taken some money. गंगा बहती है हम भी हाथ धो लें .. But 90% of this money has gone to terrorists. 'You see the disclosure made by one of the terrorists. The top terrorist says: "We take all the contracts. The Deputy Com- missioner makes money available to us. The Executive Engineer makes money available to us. The ACs make money available to us." So, all that money that is going to the State, is indirectly feeding the militancy in Kashmir. That is why you have not been able to make any dent on this issue.

The point which is very important is that it is a low-intensity war. You all say this. The very first principle of war is that you must cut the supply line of the enemy. What we are doing is that internally we ourselves are giving the supply line. Instead of cutting the line, we are feeding that line. At the border the ISI has a tremendous amount of resources at its disposal to puncture any point. After all, those of you who have seen the border from Ladakh to this, know that it is impossible to seal that border effectively because of small meadows, small huls and streams which are sometimes flowing and at some other times frozen. What is the strategy? I have got all the data. How many Kalashnikovs have been recovered ? There are 2 million Kalashnikovs between Afghanistan

and Iran and they are all flowing into Kashmir now.

I tell you that recently a book has come out It has been written by a Brigadier of Pakistan, Yusuf, who was working in the ISI. He was in charge of Afghanistan. A well thought-out strategy was planned by them for Afghanistan, and that very strategy has now been transferred to Kashmir. I will just read one line out of it to indicate to you what has been in their plan since 1988. This is very interesting and very instructive for us. It his version. He says:

> "During my four years, some 80,000 Mujahideens—soldiers of God—were trained by me. Hundreds of thousands of tonnes of arms and ammunition were distributed. Several billion dollars were spent on this immense logistic exercise. ISI camps regularly entered into Afghanistan and USSR with Mujahideens. Eventually the tactics of a thousand cuts produced a haemorrhage. That is how we succeeded."

So, we should understand what is the strategy of Pakistan or ISI. It is to cause haemorrhage. They have not got limited resources at their disposal. From the drug money alone they have collected $13 billion. There are hundreds of factories working in the no-man's land between Afghanistan and Pakistan. They are all controlled by this. All the sophisticated weapons which the ISI Mujahideens are now having have all come from what was supplied once to Afghanistan. This is a wrong diagnosis which , we have got. Since 1988, they have perfected a technique. I had been crying hoarse that this is a technique which is being applied in Kashmir all these arms and ammunition the model of the Iranian Revolution for using the mosques and fixing loudspeakers and making them work simultaneously, the Afghanistan pattern of having small sophisticated weapons and getting into every street and every village and then harassing, then internal subversion in the police, internal subversion in the medical departments, in the civil supplies department, transport department, everywhere. We have not tried to understand this pattern. That is why with all these they are succeeding, because neither do we understand the underlying motivation, nor the methods which are being employed. We are relying on our old techniques. There is a recent statement given by the Additional Director-General of the BSF that our equipment is far inferior to the equipment which they have got. With the help of the launchers that they have got they can throw grenades anywhere. That is why only two days ago they wens able to take hostages when even hundreds of policemen were there with Divisional Commissioner, with the Deputy Commissioner, with the Superintendent of Police, SDM etc. being there. Can you imagine a situation in which all the paraphernalia goes with all the security staff and they are kept hostage for five hours ? The BSF unfortunately is demoralised. They and the Army think if they take action now, it will become a human-rights issue all over the world. So, we must understand ihe power-politics of human-rights. It was part of the Pakistan's strategy. They have themselves given instructions to make reckless allegations. Do this as part of your job; demoralise the Army and confuse them. I have been saying, yes, we must take action if there is an excess and we must punish and even prosecute the officials who do anything wrong, but they must also prosecute those people who spread lies under the guise of working for human rights. Hays they prosecuted anyone for doing this because they have done immense damage to the nation? Unless we do that, we will lose the international publicity battle which we are already losing. I give you another example. I do not want to name anyone, but only four months ago a memorandum was given by the National Conference saying that at the direction of the Central Government, the previous two Governors committed genocide. I have a photostat copy of it, which I published in the latest edition of my book which shows the signatures of all those people. I suggested either prosecute them or accept that the Central Government has committed the genocide. You must decide one way or the other. They have never responded to this. These types of things were earlier published by the High Court Judge, Mr. Mufti Bahauddin, who is a Pakistani agent undoubtedly. He had filed an affidavit in the court that from 1947 India had annexed this, India had done this. The affidavit contains total Pakistani propoganda. All these documents were distributed at the Vienna conference. If you land at the Cophenhagen airport, you will get it. If you go to the U.S A, you will get it. Even the cases which have been declared by the Delhi High Court as fabricated and even when people have admitted that they are all fabricated, these are being distributed there.

Unless we know... *(Time-bell rings)* Unfortunately you are ringing the bell. There are many points...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : I am sorry.

SHRI JAGMOHAN : I will not go beyond that. I have many points. If you want to hear them, I will speak; otherwise...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : We have constraint of time.That is the problem.

SHRI KAMLA SINHA (Bihar) : Give him some more time.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Already his group has taken 19 minutes.

SHRI JAGMOHAN : I have always said this system of group timing, two minutes or three minutes to me at the end ...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : You have already taken 12 minutes.

SHRI JAGMOHAN : I may have taken.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : I am sorry, I have to run the House according to the time allotted.

SHRI JAGMOHAN : I am saying that distribution of time should be fair. If I know a subject, I should be given more time. I do not take more time on other subjects. But any now I do not want to argue; I will not go a minute beyond what you have fixed.

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रज़ी) : यस, गृह मंत्री जी ।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN); Mr. Vice-Chairman, Sir, I must express my gratitude to the hon. Members on both sides of the House who have lent their support to this proclamation which has been brought forward before this"House for approval. There is hardly any scope for giving a very lengthy explanation to all the points which have been raised by the hon. Members. I have taken note of most of the points. I must at the initial stage itself say that it may not be possible for me to respond to all the points which the hon. Members have made. But there are a few points to which I think it is absolutely necessary to respond. First, I am more than convinced that this is an issue which requires support of all the political parties.

According to my perception, Jammu and Kashmir is, in fact, a true example of the ideology that we have been preaching so far. If secularism has to live in India, Jammu and Kashmir has to remain part and parcel of this country. There can be no escape from this kind of a thing.

My approach to the entire problem would be, and I am prepared to accept this position, that we should appoint a committee consisting of all the political parties. I would like to be guided, I would like to be advised by major political parties who are functioning in our Parliament so that there is no feeling of any kind in the minds of anyone that this is being done with a political purpose. I must tell you very frankly that we should all approach this problem as a national issue and we should put our heads together and try to find out as to how best we will be able to achieve the objective that we have in our view.

Some people consider that right from 1947 our approach has been totally wrong. So also our friend, Mr. Jagmohan who has gone to the extent of saying that if the Government considers this as a kind of proxy war, then, we have to cut off the supply line. I have not been able to understand and it is still not clear in my mind as to what exactly he wants to convey. "Supply line has to be cut off". Does that mean the supply line to the people of Kashmir?

7.00 P.M.

SHRI JAGMOHAN : Supply line to the terrorist.

SHRI S. B. CHAVAN : To the terrorist ? Certainly I am prepared to accept that proposition. But my problem is to isolate the militants who have got themselves mixed. In the beginning, it was on the basis of conviction, people thought that really it was a religious war and they had to support such a cause. But now, a stage has come when people are totally fed up. that is the kind of information that we have. I am prepared to correct myself if any hon. Member were to raise a point that my information is not correct. Certainly, I am prepared to correct myself I will get it doubly checked. But my information is that people are totally fed up. Their entire economy has been shattered. They just do not have any means of livelihood. They are very keen to join the mainstream. But the fear of the gun is there very much and the kind of militants who used to be there in Jammu and Kashmir has also undergone a change. The information that the hon. Member supplied and the strategy he has pointed out—at least I had some kind of inkling

like that—is that after Afghanistan, the very force is going to be diverted towards Jammu and Kashmir and so the entire strategy will have to undergo a change. That is a point which we will have to consider with all the officers who are, in fact, concerned with the security problems and work out a strategy as to how best we will be able to confront this menace against the integrity and unity of the country.

I am not prepared to accept what my hon. friend, Shri Murli Bhandare, said to the effect that this is a Pan Islamic sort of pattern which, in fact, has been adopted. It is more than that. If it had been only a Pan Islamic sort of technology or kind of design that they had, there was some kind of a limitation. But, we cannot forget that right from 1947 Jammu and Kashmir has always been a kind of pawn in the hands of the people who would like to maintain the balance of power in the international community. You cannot deny this fart..It started from that According to my information, even now, publicly people might say all kinds of things; but the main strategy has not undergone a basic change. That is my feeling about it. They might say a number of things. But, at the same time, the basic philosophy and the basic approach which they had in mind in 1947 has not undergone any change. That is my perception about the whole thing.

Sir, there is one more point on which I would like to make myself absolutely clear. We are not opposed to the idea of delegation of powers to State Governments. Some people were putting forth the point, "Article 370 only means trying to restrict your authority to the three subjects which were given at the time of accession. Later on, through Article 370, a number of provisions were extended to Jammu and Kashmir." Now, some hon. Members are thinking in terms of reversing the entire process and they are trying to convince the Government that now a time has come when we have to divest ourselves of all the powers which we have already taken under Article 370. There is a particular procedure. If that procedure is followed, certainly we can extend the laws, the provisions of the Acts which are applicable to any of the States, to Jammu and Kashmir also. Certainly, I am not in favour of abrogation of Article 370. Let me make my point absolutely clear. But, at the same time, in the name of delegation of power, if such a kind of movement was there, this is the , main reason why I think we are not able to understand the exact history of the entire situation in Jammu and Kashmir. I cannot deny the fact that there has been rigging in that area and rigging was one of the very major factors which were responsible for youngsters taking to this kind of a line and creating a situation in which they thought that this is the only method by which they can convince all those who are concerned that rigging will not help. Ultimately, it should be through free and fair elections and whosoever comes to power, they should be in a position to accept that. I can say without any fear of contradiction that this is our line. We are not in favour of rigging; we are not in favour of imposing anyone from here. It is entirely for the people of Jammu and Kashmir to take a decision about their future. We are not going to impose anything on them. But, at the same time, they must also realise that they have to be part and parcel of this country and what is applicable in the case of others, will automatically be applicable to Jammu and Kashmir also. Might be, for some time, we can give slightly more -weightage because of certain historical factors. This is something understandable. But if you want to reverse the entire process, then, of course, it is going to be extremely difficult. Let me make my position absolutely clear on this issue.

One point which hon. Shri Sharma Ji made was that certain posts which were in possession of the Government of India till 1991, have been taken possession of by Pakistan. I have checked that information. His information seems to be based on a report, which according to the Ministry of Defence—I have checked from them—is a total distortion of facts. It is totally wrong. In fact, it is not correct. I hope he will bear this in mind. One thing which Mr. Sharma has always been raising, is about separate allocations for Jammu area, Ladakh area and the Valley area, which needs to be done and Jammu should not be neglected. So far as the neglect of Jammu is concerned, certainly, I have no objection. I am prepared to accept that Jammu needs to be given more money for their development and if there is anything which is lacking, certainly, we should try to help them out The same is the position with regard to Ladakh. Let me make this point also very clear. We had promised in 1989 when Dr. Farooq Abdullah was the Chief Minister that an Autonomous Hill Council would be established in Ladakh. It was for the entire Ladakh area and Leh. I have had very extensive discussions with them. They had, in the beginning, some kind of a social boycott of Muslims in that area. I said, 1 am prepared to accept your demand provided you give up this boycott. The boycott

should be given up. The Hindus and Muslims should work together for Leh and Kargil and if a Hill Council is demanded, certainly, we will discuss with you." And I must say we have dis- cussed the entire thing and thereafter, a final discussion is now shortly going to be held in Delhi, where I am going to invite both, the peo- ple of Kargil, as well as the people of Leh, nd take a final view about the entire thing.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh): There is no boycott in Ladakh now.

SHRI S. B. CHAVAN : No, no. The whole thing started after they gave up the boycott. That is what I said. I am in agreement with hon. Shri Sharma Ji when he said that militancy is trying to extend itself in Doda area, Kishtwar and also trying to enter in some other areas. This is a kind of strategy on which I don't think I shouldgive more details here. We are fully seized of the matter and what is required to be done will cer- tainly be done. Sir, a point was raised about the establishment of a cantonment in the Doda area. The idea of establishing a cantonment has now been given up. But some kind of an army establishment will have to be established in that area in order to check this line. Right from Anantnag this is the line of escape. They come to Doda and thereafter they try to spread them- selves. We are requesting the Ministry of Defence to set up a military establishment The only difficulty which they have pointed out—we will definitely go to their rescue—was about the handing over of the land where this military establishment has to be set up. *The* land has to be provided. But they have pat all types of con- ditions. I myself will take up the issue with the Governor and tell him that without any condi- tion the land should be in the possession of the Army authorities and let us try to help them so that they should be able to have mis Army establishment in that area and the people in that area get a feeling of confidence.

SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Sir, one clarification. When was this decision to give up the idea of establishing a cantonment taken andat what level ? When was this dicision taken? Because it was already existing.

SHRI S. B. CHAVAN: Actually, they have now totally given up the idea of this new can- tonment This is not my information. This is the information which I have collected from the Defence Ministry and I am supplying this. But I understand the point that we will have to have some kind of an establishment in that area which will give some boost to the morale of the local people. Foreigners are very much there. I am in full agreement with that. There number might differ here and there. But that clearly indicates that the same forces which have gone to Afghanistan are now trying to trickle into Jammu & Kashmir in a different form and that is why we will have to take a serious note of this.

SHRI JAGMOHAN : If you give me a minute, I would like to say one thing about the cantonment. There are, probably, two proposals which are in your mind. One thing was to set up a cantonment at Badharwa. the decision to establish a cantonment at Badharwa was an old decision, if rands were provided. Previously the State Government was not giving land on one pretext or the other. The land was acquired in 1986 during the Governor's rule and it was han-ded over to the Army. Subsequently some dif-ficulties were raised and the problem arose. That decision stands. I think what you are. referring to. i. e. Doda, is different This impression should not go with the public that we had given up the idea of establishing a cantonment at Badharwa,

SHRI S. B. CHAVAN : I wouldn't be very exact about the location part of it. But what I have stated is the general policy which the Defence Ministry has taken and they are now in favour of military stations instead of canton- ments. I am not sure about the location. Some place in that area, according to them, is morestrategic They will have to decide that But wherever it is, it will give a boost to the morale of the local people and they will feel more secure.

As regards migrants, I think I will choose some other time to give you all the information. I am in full agreement that this is one of the spheres where more needs to be done. I have no doubt in my mind about the conditions in which these people are living. They were living in palatial houses previously and now they have to live in one-room tenements, one room with a kitchen. This is the kind of situation in which they are Some of the people are living in tents and they have to change the tents three times. Instead, now we are thinking of a big pro- gramme of having one-room tenements depending upon the clearance that I get from my friend sitting behind me. If the Finance Ministry is going to help us in the matter, more one-room tenements will be constructed. It is not that they are going to be permanently there.

When they go back these tenements can be utilised either by the paramilitary forces or the local forces. So, that is what we have in view.

I am in full agreement that the Governor can- not possibly take a position that he will not mix with the people. If that is the position, certainly instructions will have to be issued that he has to go round and meet the local people. We have the Advisory Committee at the State level. We have the Advisory Committee at the district level At the moment I don't have the exact numbur of meetings which they have been able to hold so far. But I am in full agreement....

SHRI SATYA PRAKASH MALVIYA : They have met only once.

SHRI S.B. CHAVAN : If they have met only once, I am in full agreement that they should meet very frequently and give full opportunity to the members of the Advisory Committee to express their views. So, when they meet next time they should be able to report back about the action taken on some of the points which were raised by the members of the Advisory Committee. The hon. Member, Maulana Obaidullah Khan Azmi mentioned about the problem of the Chief Secretary and his relatives. I will look into the problem of the Chief Sec- retary and his relatives.

Mr. Satya Prakash Malaviya raised -a point about the Judicial Commission. He wanted to know whether they have submitted their report or not It is correct that a Judicial Commission was appointed. But still it has not given its report. We are very keen that they should com- plete their work at the earliest so that we are able to tell the world that we are not keeping quiet about any kind of excesses. We know that the Army and the paramilitary forces have to work in very difficult conditions. At the same time*w* cannot give any permission of excesses beingcommitted against the local people.

It will make our position all the more worse. It is always necessary to use force against those against whom it is called for, not against those people who ate innocent. We should not unnecessarily try to antagonise them.

श्री मोहम्मद आज़म : जे० के० एल० एफ० के साथ बातचीत की कोई सूरत निकली है ?

شری محمد اعظم: جے۔کے۔ایل۔ایف۔ کے ساتھ بات چیت کی کوئی صورت نکلی ہے

SHRI S. B. CHAVAN: Whether it is JKLF or any militant group, we have no objection to talk to them provided they accept our two con- ditions. One is, "give up violence" and the second is "accept the Indian Constitution". These are the two conditions. If they accept both these conditions, let them come and discuss the matters with us. My only difficalty is, there are a large number of splinter groups. To whom to talk is the main point. In the case of Punjab we did take this position that we will have to go for elections. Thereafter whosoever comes to power we are prepared to discuss with them. I would not like to give any wrong impression that new conditions are quite congenial for elections in Jammu and Kashmir. It is far from the truth. At least I don't hold that view. I must state very frankly that a large number of things will have to be done. People will have to be taken into confidence. If not total normalcy at least near normalcy will have to be created to hold elec-tions in that area. That is why it becomes all the more necessary that all of us should sit together and try to find out collectively as to how best we can solve these problems. These were the few points which I wanted to submit before the hon. Members. I against thank the hon. Members for participating in the deabte".

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने बहस में हिस्सा लिया और खासतौर से कश्मीर की कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों के साथ-साथ वहां की आर्थिक स्थिति और वित्त के बारे में जिक्र किया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि राज्य का जो योजनागत खर्च 1993-94 के लिए 880 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यह खर्च 1992-93 में 620 करोड़ रुपए था। इस योजना खर्च में जो केन्द्रीय सहायता का हिस्सा है वह 782.81 करोड़ रुपए है और जो यह 880 करोड़ रुपए का योजनागत खर्च है, इसके लिए जो खास मुख्य मद है, उस में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा मदद दी गई है। उस तुलनात्मक दृष्टिकोण से जो चार-पांच खास खास मदें हैं, उनके बारे में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा। कृषि के क्षेत्र में जो 1992-93 में 78.63 करोड़ रुपया था, वह 1993-94 में 87.59 करोड़ रुपया रखा गया है जिसके अंदर 11.4 परसैंट की वृद्धि है। ऊर्जा के अंदर 1992-93 में 120.43 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जो 1993-94 में 250.21 करोड़ रुपए रखा गया है, इसके अंदर 117.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उद्योग एवं खनिज के लिए गतवर्ष 33.91 करोड़ रुपए

†] Transliteration in Arabic Script

का प्रावधान था, वह बढ़ाकर 74.74 करोड़ रुपए का किया गया है, इसके ऊपर 120.4 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । यातायात में जो गतवर्ष 49.33 करोड़ का प्रावधान था, वह 1993-94 में बढ़ाकर 69.70 करोड़ रुपए किया गया है, जिसमें 41.3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । सामाजिक सेवाएं, जिनमें गतवर्ष 220.90 करोड़ रुपए का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर 247.92 करोड़ किया गया है, इसमें 12.2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । इसके अतिरिक्त वर्ष 1992-93 में रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट और एक अंतर मंत्रालय समिति की जो सिफारिश थी, उसके मुताबिक 222.53 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दी गई है । यह जो 880 करोड़ रुपए का योजनागत खर्च है, इसका जो टोटल 11 मद हैं, उनमें किस तरह से इसका अलग-अलग प्रावधान किया गया है, वह भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा । कृषि एवं सहायक क्रियाओं के लिए 87.59 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो कुल का 9.95 प्रतिशत है । ग्रामीण विकास के लिए 29.68 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो कुल का 3.36 प्रतिशत है । विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के लिए 33.35 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो कुल का 4.02 प्रतिशत है । सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए 46.56 करोड़ का प्रावधान है जो कुल का 5.29 प्रतिशत है । ऊर्जा के लिए 250.21 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो कुल का 28.43 प्रतिशत है । उद्योग तथा खनिज के लिए 74.57 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो कुल का 8.49 प्रतिशत है । यातायात के लिए 69.70 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो कुल का 7.92 प्रतिशत है । विज्ञान एवं तकनीकी के लिए 2.27 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो कुल का .26 प्रतिशत है । सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए 28.46 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो कुल का 3.22 प्रतिशत है और सामाजिक सेवाओं के लिए 247.92 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो कुल का 28.17 प्रतिशत है और सामान्य सेवाओं के लिए 7.77 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो कुल का .89 प्रतिशत है । तो इस प्रकार से यह जो 880 करोड़ रुपए का योजनागत खर्च है, इसका अलग अलग मदों के ऊपर बंटवारा किया गया है जिसमें खास तौर से जो प्रमुख मद हैं, जिनसे राहत पहुंचाई जा सके, विकास किया जा सके, उनका प्रमुख रूप से उनमें ध्यान रखा गया है । राज्य की पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य की गरीबी को हटाना तथा संतुलित क्षेत्रिय विकास के लिए, सेल्फ सस्टेनिंग इकोनमी के लिए आधार बनाना रहा है । राज्य में पावर उद्योग, यातायात आदि क्षेत्रों में निरंतर विनियोग तथा इसके साथ-साथ सामाजिक एवं सामुहिक क्षेत्रों पर भी जोर दिया गया है । इसी कारण से कुल योजनागत खर्च का 28.17 प्रतिशत सामाजिक सेवा क्षेत्रों पर खर्च किया गया है । कुल निवेश का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जल-वितरण पर खर्च करने का प्रावधान रखा गया है । ऊर्जा के क्षेत्र में कुल योजनागत खर्च का 28.43 प्रतिशत 1993-94 के लिए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है । महोदय, सुरक्षा संबंधी खर्चों के ऊपर वृद्धि के कारण सरकार को थोड़ा वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । राज्य सरकार को ऋणों की वसूली के स्थगन द्वारा योजनागत मद से गैर योजनागत मद में फंड का डाइवरज़न करके तथा 150 करोड़ रुपए की नकद सहायता प्रदान करके राहत प्रदान की गई है । इसके साथ ही साथ चालू वर्ष में राज्य सरकार को खर्च संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं । माननीय शर्मा जी ने एक बात पूछी थी, उसका आगे मैं विस्तृत रूप में तो उत्तर दूंगा, लेकिन खास तौर से जो खर्च किया जा रहा है, जो हमारे लक्ष्य थे 1992-93 में और उसमें क्या प्राप्तियां रही हैं और उसके अनुरूप 1993-94 में हमने क्या लक्ष्य रखे हैं, वह भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा । खास तौर से खाद्यान्न उत्पादन के लिए 1992-93 के ऊपर जो 16.09 लाख टन की हमारी वास्तविक प्राप्ति है और उसी आधार पर 1993-94 में हमने 19 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया है । फल उत्पादन की 1992-93 की जो 8.60 लाख टन प्राप्ति है और उसी आधार पर 1993-94 के लिए 8.73 लाख टन का हमने प्रावधान किया है । रासायनिक खाद की गत वर्ष की जो 93 हजार टन प्राप्ति है और उसी आधार पर 1993-94 के लिए हमने 98 हजार टन का लक्ष्य रखा है । गोबर गैस प्लांट में 1992-93 की जो प्राप्ति है, उसी आधार पर हमने 1993-94 में 190 प्लांट का लक्ष्य रखा है । दुग्ध उत्पादन में 1992-93 की जो हमारी 6 लाख टन प्राप्ति है और इसी आधार पर हमने 1993-94 में 6.30 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया है । मछली उत्पादन में वर्ष 1992-93 की जो 14.50 हजार टन प्राप्ति है और उसी आधार पर हमने 15 हजार टन का लक्ष्य रखा है । गरीबी उन्मूलन के लिए आई० आर० डी० पी० के अंतर्गत 1992-93 में जो लाभार्थियों की संख्या 7 हजार लोगों की है और उसी आधार 1993-94 में 8 हजार का लक्ष्य निर्धारित किया है । ग्रामीण सेनिटेशन के लिए गांव की संख्या वह 1992-93 की प्राप्ति 739 है और 1993-94 में 120 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । जवाहर रोजगार योजना के ऊपर 62.87 लाख मानव दिवस हमने प्राप्त किए हैं और जो लक्ष्य निर्धारित किया है 1993-94 के लिए वह 70 लाख मानव दिवस है । पावर इंस्टाल केपेसिटी के ऊपर 315.22 मेगावाट 1992-93 में प्राप्त किया है और 1993-94 में हमने 427.51 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है । नए स्कूलों की स्थापना जिसमें प्राथमिक से लेकर 10+2 तक के 1992-93 में 328 हैं और 1993-94 के लिए हमने 442 का लक्ष्य रखा है । 1992-93 में हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 12 स्थापित किए हैं और 1993-94 के लिए हमने 20 का लक्ष्य निर्धारित किया है । 1992-93 में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया है और 1993-94 में चार का लक्ष्य निर्धारित किया है । जल वितरण की अतिरिक्त गांव की संख्या जो 1992-93 में दी गई है वह 129 है और लक्ष्य 1993-94 में 192 का रखा गया है । स्वरोजगार के लिए जो संख्या है वह 1800 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है । इसके साथ ही साथ ....(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल (बिहार) : यह आंकड़ें तो और आप दिखा भी सकते थे और हम पढ़ भी सकते थे । मुश्किल जो सबसे बड़ी है वह आस्पेक्ट से कश्मीर पर की गई है । अगर बराहे मेहरबानी आप हमको एक बात बतायें कि वहां की बीमारी में एक अन-एम्प्लायमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है । तो आपने

कितने नए जॉब्स क्रिएट किए हैं, खासकर पढ़े-लिखे लोगों के लिए—इंजीनियर्स वगैरह के। उपसभाध्यक्ष जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत दिनों पहले से लेकर मेरा संबंध कश्मीर के साथ रहा है। मैं इस पर आज बोला नहीं हूं लेकिन एक बात मैं कहना चाहता था कि जी० एम० सादिक जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मेरी प्रजेंस में इंदिरा जी को एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि:

"There is much spent on Kashmir, but very little spent in Kashmir."

उससे जो अन-एम्प्लोयमेंट की प्रोब्लम पैदा हुई है उसके लिए आपने कुछ किया है? कितने नए जॉब्स क्रिएट किए हैं?

डा० अबरार अहमद : मुझे आश्चर्य हुआ कि गुजराल साहब जैसे माननीय सीनियर सदस्य ने सवाल पूछा। मैंने जितने भी कार्यों के बारे में बताया, लक्ष्य निर्धारण के बारे में बताया और लक्ष्यों की प्राप्ति बताई, पैसों का अलग-अलग विभाजन जिस प्रकार से किया गया है, वह बताया है। यह सारे के सारे ही जॉब्स के लिए हैं। यह कौन करेगा इन कामों को? कौन, इससे काम करके यह रिजल्ट लाएगा? कौन वहां उत्पादन करेगा? वहां कौन स्कूलों के अंदर पढ़ाएगा? वहां कौन स्वास्थ्य केन्द्रों के अंदर काम करेगा? जितना पैसा खर्च किया जा रहा है, इतने लम्बे-चौड़े मैंने आंकड़े बोले हैं, वह सब वहां पर एम्प्लोयमेंट देने के लिए, वहां के विकास के लिए, वहां पर आवश्यक कामों के लिए ही इस पैसे का प्रावधान रखा गया है और यह लक्ष्य उन्हीं के माध्यम से प्राप्त किए हैं और लक्ष्यों का जो निर्धारण किया है, वह उन्हीं के लिए है। वहां यह कोई दरख्त के लिए, जमीन के लिए थोड़ी सब कुछ है, वहां रहने वालों के लिए है।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Sir, let him say how many more jobs will be created by these efforts.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): If any point remains, after the completion of his speech you can put questions. So, don't interrupt him now; he will not be able to complete his reply.

डा० अबरार अहमद : मुझे अपना कांक्लूड करने दीजिए। माननीय शर्मा जी ने इसके साथ ही साथ कुछ रेवेन्यू के बारे में भी सवाल उठाए थे कि वहां से क्या कुछ रेवेन्यू कलक्शन हो रहा है या रेवेन्यू कलक्शन प्रारम्भ हुआ है? तो उस संदर्भ में मैं माननीय शर्मा जी को यह बताना चाहूंगा कि वहां जो 1992-93 के लिए कुछ मदें हैं, हमने रेवेन्यू कलक्शन का जो लक्ष्य रखा था उससे भी ज्यादा रेवेन्यू कलक्शन हुआ है। खास तौर से बिक्री कर का 1992-93 में रेवेन्यू कलेक्शन का जो लक्ष्य था वह 69.94 करोड़ रुपए का था जब कि वास्तव में हमें जो मिला वह 76.95 करोड़ रुपया है। उसी आधार पर......

श्री कृष्ण लाल शर्मा : रेवेन्यू कलेक्शन कितना है। काश्मीर घाटी का मैंने पूछा था।....

डॉ० अबरार अहमद : रेवेन्यू कलेक्शन ही आप को पढ़कर मैं बता रहा हूं....

श्री कृष्ण लाल शर्मा : आप टोटल स्टेट का बता रहे हैं, मैंने काश्मीर घाटी का पूछा है...

डॉ० अबरार अहमद : अलग अलग तो मेरे पास नहीं है, यह पूरी स्टेट का है जो मैं आपको बता रहा हूं।

श्रीमन, उत्पादन जो 1992-93 का हमारा लक्ष्य था वह 59.34 करोड़ का था और वास्तव में हमें प्राप्त हुआ 59.25 करोड़ और 1993-94 के लिए 62.25 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। चुंगी का लक्ष्य जो 41.48 करोड़ का था उसकी जगह 50.20 करोड़ प्राप्त हुआ और जो लक्ष्य 1992-93 के लिए रखा है वह 52.60 करोड़ का है। अन्य के लिए 1992-93 में 22.23 करोड़ का लक्ष्य था, इससे 20.34 करोड़ की प्राप्ति हुई और 1993-94 के लिए 22.16 करोड़ का लक्ष्य रखा है। इस प्रकार से 187.70 करोड़ का हमने 1992-93 का लक्ष्य रखा था जब कि वास्तविक प्राप्ति हमारी 206.74 करोड़ रुपए की हुई है।

इसके साथ ही साथ जो माननीय शर्मा जी पूछ रहे थे कि वहां पर विस्थापितों के संबंध में क्या किया गया है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1992-93 में जो प्रावधान हमने रखा है। नकद सहायता के संबंध में 20 करोड़ रुपए और मुफ्त सहायता के संबंध में 5 करोड़ रुपए और नागरिक सुविधाओं, क्षेत्रीय सुविधाओं आदि के लिए एक करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इस प्रकार से 26 करोड़ रुपए का प्रावधान विस्थापितों के संबंध में रखा गया है।

इसके साथ ही साथ जिन प्रवासियों के संबंध में शर्मा जी पूछ रहे थे वह मैं आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर जो 8700 प्रवासी परिवार हैं अधिकांश उनमें से अपने रिश्तेदारों और मित्रों के यहां रह रहे हैं। 350 परिवार दिल्ली में एन० डी० एम० सी० के सामुदायिक केन्द्रों आदि में स्थापित कैंपों में रह रहे हैं। उनमें से प्रत्येक को 500 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति दिए जा रहे हैं और 500 रुपए का सूखा राशन दिया जा रहा है। जो कैंपों में नहीं रह रहे हैं उन्हें एक हजार रुपए प्रति माह नकद दिये जा रहे हैं।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या आप इसको पर्याप्त मानते हैं?...

डॉ० अबरार अहमद : यह प्रश्न नहीं है, जो मैं दे रहा हूं या दिया जा रहा है, वह मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। पर्याप्त है या नहीं, किसको कितना चाहिए, यह सवाल अलग है, यह बहस की बात है।

इसके अलावा 4000 बच्चों को सेंट्रल स्कूलों में प्रवेश दिया गया है। काफी छात्रों को कालेज आदि में प्रवेश के लिए कहा गया है। जम्मू के अंदर प्रवासियों को सहायता के संबंध में मैं

माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि चार या इससे अधिक वाले परिवार को 300 रुपए प्रति व्यक्ति, अधिकतम एक हजार रुपए प्रति माह और मुफ्त सूखा राशन जो 300 रुपए प्रति माह की राशि के बराबर हो, दिया जा रहा है । चिकित्सा सुविधाएं प्रवासियों के बच्चों के लिए कैंप, विद्यालय और कालेजों में खोले गए । इसके अंदर राज्य के प्रवेश को निरुत्साहित करने के लिए दिल्ली और जम्मू के अंदर जो राहत दी जानी वाली है उसके अंदर अंतर रखा गया है । इसके साथ ही साथ जम्मू के अंदर प्रवासियों की सहायता के लिए, जहां जो 27000 प्रवासी परिवार है, उनके लिए 1900 एक कमरेवाले मकान बना दिए गए हैं, 300 और मकान निर्माणाधीन हैं और एक हजार ऐसे मकान बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है । 800 ऐसे परिवार सरकारी इमारतों और सरकार द्वारा लगाए गए तंबुओं के अंदर निवास कर रहे हैं ।

इस के साथ ही साथ कारगिल के बारे में माननीय सदस्य ने सवाल उठाया था । लद्दाख, कारगिल के बारे में माननीय सदस्य ने सवाल उठाया था । लेह लद्दाख और कारगिल के संबंध में वर्ष 1992-93 में 79.61 करोड़ रुपए की तुलना में चालू वर्ष में 880 करोड़ रुपए का आवंटन का मैंने आपको बताया । उसमें 35.35 करोड़ रुपए की व्यवस्था ले ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र के लिए आवंटन की राशि शामिल नहीं है । तो इस प्रकार जहां तक इस पैसे के दुरुपयोग के संबंध में माननीय सदस्य ने कहा था, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जहां भी पैसे के दुरुपयोग के संबंध में रिपोर्ट मिलती है, तत्काल कार्यवाही की जाती है । हाल ही में अनंतनाग जिले में ए० आर० वाइ० की निधि के गबन का मामला उठा था । राज्य सरकार ने अनंतनाग जिले के उपायुक्त सहित 14 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है और उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है तो जहां भी ऐसी रिपोर्ट मिलती है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है । तो इन शब्दों के साथ सब जानकारियां माननीय सदस्यों ने जो सवाल पूछे थे उनकी मैंने दी । मैं आग्रह करूंगा कि इसको स्वीकार किया जाए और इस बिल को लौटाया जाए ।

एक माननीय सदस्य : जितने निर्दोष लोग मारे गए हैं उनके आंकड़े बता दीजिए ।...

डॉ० अब्रार अहमद : जब बिल की बात करता हूं तो दूसरा सवाल पूछते हैं, जब दूसरी बात करता हूं तो मरे हुए लोगों की बात करते हैं

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : The hon. Member has informed about the amounts allotted to several projects. Several hon. Members had raised the issue of employment opportunities for which the hon. Minister said that after the allocation of the amounts for the projects, the jobs will be automatically created when these projects are implemented. Sir, want to know from the hon. Minister as to how many additional jobs he expects to create with the enhanced amounts allocated for various projects during this financial year.

डॉ० अब्रार अहमद : मान्यवर, मैंने बहुत विस्तृत रूप में जितने लक्ष्य निर्धारित किये हैं 1993-94 के लिए हर क्षेत्र के अन्दर, वह बताये हैं । उससे बिलकुल स्पष्ट हो जाता है । प्रतिशत के अन्दर बताये हैं और संख्या में भी बताये हैं । अब गिनकर तो मैं बताने से रहा कि कितने लोगों को उसके अन्दर और रोजगार मिलेगा ।

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : I shall now put the Statutory Resolution moved by Shri S. B. Chavan to vote. The question is:

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation issued by the President on the 18th July, 1990, under article 356 of the Constitution, in relation to the State *of* Jammu and Kashmir, for a further period of six months with effect from the 3rd September, 1993."

The motion was adopted

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : I shall now put the motion moved by Dr. Abrar Ahmed to vote. The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jammu and Kashmir, for the services of the financial year 1993-94, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

डॉ० अब्रार अहमद : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को लौटाया जाये ।"

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Now there is a slight change in the order of the Agenda. I request Mr. Salve to move the Statutory Resolution.